



# पायनियर

नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित



भारत में रोहिण्या  
घुसपैठ कई गुना  
बढ़ गई है  
राष्ट्रीय-10

www.dailypioneer.com

## शाह का दावा, केरल को चेताया था, मुख्यमंत्री ने किया इनकार



वायनाड में भारी भूस्खलन के बाद बुधवार को राहत और बचाव कार्य जारी रहा।

### ● भारी भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 200 पार पहुंची

कुमार चेल्लपन। नई दिल्ली/कोच्चि

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि केरल में भारी बारिश की अग्रिम चेतावनी राज्य सरकार को वायनाड में घातक भूस्खलन से कम से कम एक सप्ताह पहले जारी की गई थी, जिसने मौत और विनाश के भारी निशान छोड़े हैं।



दूसरी ओर केरल सरकार ने आरोप लगाया कि मौसम विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियां वायनाड जिले में हुई

बारिश और भूस्खलन के बारे में प्रारंभिक चेतावनी जारी करने में बुरी तरह विफल रही। शाह ने संसद को नवीनतम जानकारी देते हुए कहा, 18 जुलाई को अनुमान लगाया गया था कि केरल के पश्चिमी तट पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। 25 जुलाई को पूर्वानुमान था कि भारी बारिश होगी। 23 जुलाई को ही एनडीआरएफ की आठ टीमों को इस क्षेत्र में भेजा गया था। केंद्र ने किसी भी आपदा की स्थिति में केरल सरकार की सहायता के लिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की आठ टीमों भेजी थीं।

## कोर्चिंग सेंट्रों को नरेला और रोहिणी में स्थानांतरित करेंगे

### ● तीन आईएसएस उम्मीदवारों की मौत के बाद दिल्ली सरकार बना रही योजना

राजेश कुमार। नई दिल्ली

पुराने राजिंदर नगर इलाके में राजऊ आईएसएस अध्ययन केंद्र के बेसमेंट में डूबने से तीन आईएसएस उम्मीदवारों की दुखद मौत के बाद दिल्ली सरकार नरेला और रोहिणी में कोर्चिंग सेंट्रों को स्थानांतरित करने और इसे एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कोर्चिंग सेंट्रों के नियमन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति कोर्चिंग संस्थानों को विभिन्न स्थानों से सुनियोजित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की कार्ययोजना तैयार करेगी। राजऊ कोर्चिंग सेंट्र के पास नागरिक अधिकारियों और 'कोर्चिंग माफिया' के खिलाफ लगातार चौथे दिन आईएसएस अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थामस ने बुधवार को तीन छात्रों की मौत के मामले में नगर



नई दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में हाल ही में तीन छात्रों की डूबने से हुई मौत के बाद धरना दे रहे छात्रों से बातचीत करता एक पुलिसकर्मी। फोटो: रंजन डिग्री

निवारण नकद लेनदेन पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि एक पोर्टल स्थापित किया जाए, जिसमें शहर के सभी कोर्चिंग संस्थानों और नामांकित छात्रों के आधार आधारित लॉग-इन क्रेडेंशियल हों। इससे एक पारदर्शी डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी जो सरकार को समय-समय पर नीतिगत ढांचे को आकार देने में मदद करेगी। समिति में कोर्चिंग संस्थानों के पांच से छह प्रतिनिधि, छात्र और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति सभी मापदंडों को पूरा करते हुए एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए विनियमन, (शेष पेज 9)



### ईरान में हमास नेता हनिह की हत्या, इजराइल पर शक पीटीआई। केरल

ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद हमास नेता इस्माइल हनिह की हत्या कर दी गई। ईरान और उग्रवादी समूह हमास ने बुधवार तड़के यह जानकारी दी। हमास ने अपने राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख की मौत के लिए इजराइल के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, ईरान के अर्धसैनिक बल रिजोल्वशनरी गार्ड ने कहा कि वह हनिह की हत्या की जांच कर रहा है। उसने यह नहीं बताया कि हत्या कैसे हुई और हनिह को किसने मारा। फिलहाल किसी ने भी हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसका शक इजराइल पर है, जिसने सात अक्टूबर को देश में हुए अप्रत्याशित हमले को लेकर हनिह और हमास के विभिन्न कमांडरों को मारने का संकल्प लिया था। इजराइल ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमास ने बताया कि हनिह समूह के अन्य अधिकारियों और हिजबुल्ला तथा सहयोगी समूहों के अन्य अधिकारियों के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने (शेष पेज 9)

## पूजा खेडकर अब आईएसएस अफसर नहीं

### ● यूपीएससी ने चयन रद्द किया, भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने पर लगाई रोक

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बुधवार को एक प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) अधिकारी पूजा मनोरमा दिल्ली खेडकर को 2022 सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें आयोग की किसी भी भविष्य की परीक्षा में बैठने से रोक दिया। अनुमति से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित होकर नियमों का उल्लंघन किया था। इसमें कहा गया है कि सीएसई-2022 (सिविल सेवा परीक्षा-2022) के लिए उनकी अर्न्तम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें भविष्य की सभी यूपीएससी परीक्षाओं या चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। यूपीएससी ने खेडकर को 18 जुलाई को अपनी पहचान फर्जी बनाकर परीक्षा नियमों में प्रदान की गई अनुमति सीमा से परे प्रयासों का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें 25 जुलाई तक नोटिस पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक



यूपीएससी की अध्यक्ष बनी प्रीति सूदन नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत में मनोज सोनी के यूपीएससी के शीर्ष पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र ने बुधवार को पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। सूदन, जो वर्तमान में यूपीएससी के सदस्य हैं। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, राष्ट्रपति ने... यूपीएससी के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए यूपीएससी की सदस्य प्रीति सूदन को नियुक्त को 1 अगस्त, 2024 से अगले आदेश तक या 29 अप्रैल, 2025 तक, जो भी पहले हो, मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश के 1983 बैच के आईएसएस अधिकारी, सूदन ने जुलाई 2020 तक तीन साल तक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

का और समय मांगा। यूपीएससी ने उन्हें अपनी बात रखने के लिए 30 जुलाई को दोपहर 3.30 बजे तक की अनुमति दी। एक बयान के अनुसार, यूपीएससी ने कहा कि उसने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उसे सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 18 जुलाई, 2024 को सिविल सेवा परीक्षा-2022 (सीएसई-2022) की अर्न्तम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार सुश्री पूजा मनोरमा दिल्ली खेडकर को धोखाधड़ी के लिए एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। उसने अपनी फर्जी पहचान दिखाकर परीक्षा नियमों में दी गई स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास किए। इसमें कहा गया है कि 34 वर्षीया को 25 जुलाई तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक का समय मांगा। यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई तक का समय दिया और स्पष्ट किया कि यह अंतिम अवसर था। और समय में कोई और विचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें यह भी बताया गया कि अगर समय सीमा तक कोई जवाब नहीं मिला तो यूपीएससी कार्रवाई करेगी। पैराल ने बयान में कहा, उन्हें समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रही। पैराल ने कहा, यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की (शेष पेज 9)



## बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी वापस हो: नितिन गडकरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वापस लेने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में गडकरी ने नागपुर डिवाजन जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया, जिसने उन्हें बीमा उद्योग के मुद्दों के संबंध में एक जापन सौंपा था। जापन का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा, जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।



इसके अलावा, उन्होंने कहा कि संघ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वापस लेने से संबंधित है। जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम दोनों 18 प्रतिशत जीएसटी दर के अधीन हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा, इसी तरह, चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी व्यवसाय के इस खंड के विकास में बाधक साबित हो रहा है जो सामाजिक रूप से आवश्यक है। उन्होंने कहा, उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए उचित सत्यापन के साथ नियमों के अनुसार बोझिल हो जाता है।

## जाति मुद्दे पर छिड़ी जुबानी जंग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमले के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर बुधवार को सत्तारूढ़ दल भाजपा और विपक्षी सदस्यों के बीच जुबानी जंग हुई, जिसके कारण संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को लोकसभा में भाजपा सांसद ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिसको 'जाति का पता नहीं वह जाति जनगणना की बात करते हैं।' कांग्रेस ने ठाकुर और प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है और दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाकुर के भाषण को सोशल मीडिया पर साझा करके 'संसदीय विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन' को बढ़ावा दिया, विपक्षी सांसदों ने ठाकुर के भाषण को दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का अपमान बताया।



नई दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में भाग लेने पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।

कांग्रेस ने ठाकुर के भाषण को सोशल मीडिया पर साझा करके 'संसदीय विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन' को बढ़ावा दिया, विपक्षी सांसदों ने ठाकुर के भाषण को दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का अपमान बताया। संसद में विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने कहा कि गांधी परिवार को जाति शहादत है लेकिन बीजेपी-आरएसएस इसे कभी नहीं समझेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी बेंच के विरोध पर अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सांसदों को आश्वासन दिया कि टिप्पणियों को हटा दिया जाएगा। भाजपा ने जाति विवाद को बढ़ाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पूछने में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया, जिसमें कथित तौर पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा की गई टिप्पणियों के अंश थे, जिन्हें सभापति ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था। लोकसभा में कांग्रेस के दलित सांसद चन्नी ने स्पीकर ओम बिरला को एक नोटिस सौंपकर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रक्रिया के नियमों के नियम 222 के तहत विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी कहती रही है कि बीजेपी के लोगों के दिल में एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। राजद के मनोज झा ने कहा कि ठाकुर ने अपनी समर्त (शेष पेज 9)

## झमाझम बारिश से तर हुए दिल्ली-एनसीआर

### ● भीषण उमस से मिली राहत तो ट्रैफिक जाम, बिजली कटौती से परेशान हुए लोग

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

बुधवार शाम को तेज और अचानक बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी और नोएडा तथा गाजियाबाद सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों ने राहत महसूस की। पिछले कई दिनों से लोग यहाँ भीषण उमस का सामना कर रहे थे। हालांकि तेज बारिश के कारण



नई दिल्ली में पूसा रोड पर भारी बारिश के बाद जलजमाव के बीच महिला को सड़क पार करता एक पुलिसकर्मी।

लोगों को इससे जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम हो गया था बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ा।

शाम 7.30 बजे से 8 बजे के बीच इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से कम से कम 10 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। शहर को रेड अलर्ट पर रखा गया है और नेशनल फ्लड गार्डेंस बुलेटिन ने दिल्ली को 'चिंता के क्षेत्रों' की सूची में शामिल किया है। पूरी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में मध्यम से भारी बारिश के कारण, चिराग दिल्ली, साकेत सहित कई स्थानों पर जलभराव के कारण काम से अपने घरों को वापस जाते समय यात्रियों को सड़क के बड़े हिस्से पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इन इलाकों में सैनिक फार्म, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन,

छत्ता रेल चौक, मिंटो ब्रिज, आईटीओ, जनपथ, करोल बाग, गफफार मार्केट, नौरोजी नगर, पंत मार्ग, निगम बोध घाट, कर्नाट प्लेस और मयूर विहार शामिल हैं। शनिवार शाम को हुई बारिश के कारण राजऊ कोर्चिंग सेंट्र के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें तीन आईएसएस उम्मीदवारों की जान चली गई थी, बुधवार को बारिश के कारण संस्थान के बाहर एक बार फिर जलभराव हो गया। स्थानीय विधायक दुर्गा शपाठक मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि निचले इलाके से पानी पंप कर निकाला गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी सोशल मीडिया (शेष पेज 9)

## भोले के भक्त



नई दिल्ली में बुधवार को सावन के गहौने में शिवभक्त कांठड़े पतिर गंगाजल लेकर जाते हुए।

# दूधेश्वरनाथ मंदिर के कपाट 24 घंटे के लिए खुलेंगे

पर्यनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

सावन शिवरात्रि के नजदीक आते ही सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में कांबडियों की भीड़ बढ़ने लगी है। मंदिर के आसपास का वातावरण भी भगवान दूधेश्वर के जयकारों से गूंज रहा है। कांबडियों की भीड़ को देखते हुए गुरुवार से मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे। सफाई, आरती व भोग के लिए ही कपाट बंद होंगे।



भगवान दूधेश्वर का जलाभिषेक कर रहे हैं। 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का जल अपरान्ह 3.30 बजे से चढ़ना शुरू होगा। उससे पहले त्रयोदशी का जल चढ़ेगा। मंदिर के मीडिया प्रभारी एसआर सुथार ने बताया कि शुरुवार को मंदिर में लाखों कांबडिए व शिवभक्त भगवान का जलाभिषेक करेंगे। पुलिस प्रशासन व नगर निगम

शिवलिंग पर जल चढ़ रही महिला की सोने की चेन लूटी नोएडा। थाना सूरजपुर क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन उसे समय लूट ली जब वह शिव मंदिर में जल चढ़ा रही थी। थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात को आंचल शर्मा निवासी डेल्टा-2 ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी मां गीता शर्मा डेल्टा दो स्थित शिव मंदिर में जब शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी तभी एक व्यक्ति ने झपट्टा मारकर उनकी मां के गले से सोने की चेन लूट ली।

विक्रम सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन का सहयोग मिल रहा है।

# झुगगी में लगी आग से तीन बच्चियों की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल

## अग्निशमन दल को बुधवार सुबह चार बजे आग लगने की मिल थी सूचना

● इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया

पर्यनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा जिले कोतवाली फेज वन क्षेत्र में आग लगने से तीन बच्चियों की मौत हो गई और परिवार का मुखिया भी झुलसा। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए दिल्ली के हायर सेंटर सफदरजंग में रेफर किया गया है।



घर में रखा सामान आग से हुआ राख।

डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे फायर सर्विस को सूचना मिली थी, की सेक्टर 8 स्थित झुगगी के एक कमरे में आग लग गई है। यह मकान संदीपा है, जिसमें दौलत राम पत्नी और तीन बेटों 10 वर्षीय आस्था, 7 वर्षीय नैना और 5

मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे फायर सर्विस को सूचना मिली थी, की सेक्टर 8 स्थित झुगगी के एक कमरे में आग लग गई है। यह मकान संदीपा है, जिसमें दौलत राम पत्नी और तीन बेटों 10 वर्षीय आस्था, 7 वर्षीय नैना और 5

नोएडा ने बताया कि आग बुझाने के बाद जांच के दौरान पाता चला कि कमरे में पांच लोग सोए हुए थे जिसमें तीन बच्चियों की इस घटना में झुलसने से तीन बच्चियों की मौत हो गई, जबकि दौलतराम भी बुरी तरह झुलस गए उन्हें अस्पताल में भर्ती

कराया गया। जहां से उनकी गंभीर हालत देखते हुए दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। मौके पर फायर और पुलिस के अधिकारी मौके मौजूद हैं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आग लगने के कारणों की जांच के साथ कार्रवाई की जा रही है।

**KVB Karur Vysya Bank**  
दिल्ली अतिरिक्त बसुली शाखा, नं. 6, तीसरी मंजिल, मेट्रो विस्तर नं. 80 के विपरीत, पूसा रोड, कपूरल बाग, नई दिल्ली 110005  
फोन: 782919520 फैक्स: 011-3500283

**ई-नीलाामी सूचना, दिनांक 06.09.2024 को ई-नीलाामी**

**सफेदी-सी अधिनियम, 2002 के तहत अपल संपत्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना**

वित्तीय आरक्षणों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निम्नलिखित उपकरणों की सुरक्षित आरक्षणों पर कर वेंचर बैंक लिमिटेड की निम्नलिखित शाखाओं के निम्नलिखित उपकरणों/गारंटियों से बकाया सुरक्षित अर्थात् की बसुली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिए जाने के अनुरूप है।

यदि अधोहस्ताक्षरी ने अपल संपत्तियों की ई-नीलाामी करने का निर्णय लिया है, इसलिए निम्नलिखित आरक्षणों को "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है", तथा "जो कुछ भी है" और "बिना सहारे के" आधार पर खरीदने के लिए ई-निर्वाह के माध्यम से प्रस्तावित किया जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का प्रकार	आवधिक मूल्य (₹.00,000)	ईसपीटी मूल्य (₹.00,000)	सम्पर्क व्यक्ति का फोन/ईमेल
1	मैसर्स एच एलएच/के	लॉरेस रोड	रिहायशी भूखि एवं खन, जॉबि मुनिनीयन नं. एल-2/28, पूसा रोड प्लॉट नं. 28, सूर्य प्रभम ताल, शाही नगर, दिल्ली-110052	रिहायशी प्लॉट	60,00,000	6,00,000	श्री हिमांशु रंजन 7765046680 himanshurajan@gmail.com
2	श्री राकेश सिंह	लॉरेस रोड	रिहायशी प्लॉट नं. 137, 137बी नॉर्थ, टावर नं. डी-4, सेक्टर 24, अवलौली हार्टडर, ग्नी अलवरपुर, धाकंडवा, रेवाड़ी हरियाणा-123110	रिहायशी प्लॉट	28,35,000	3,00,000	श्री हिमांशु रंजन 7765046680 himanshurajan@kvbmail.com

उपकरणों का विवरण: 1. लॉरेस रोड शाखा, उपकरणों का नाम - (1) मैसर्स एच एलएच/के, प्रोपर्टी/प्लॉट/प्लॉट नं. 28, रिहायशी प्लॉट/28ए, ब्लॉक एल-2, शाही नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली - 110052, (2) श्री विद्या पराम, प्रोपर्टी/प्लॉट/प्लॉट नं. 28, रिहायशी प्लॉट/28ए, ब्लॉक एल-2, शाही नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली - 110052 (3) श्रीमती राज बाबा, (गारंटी) पत्नी श्री विद्या पराम, निवासी 557/37 ओकर नगर, त्रि नगर, दिल्ली - 110035 और कुल देय. दिनांक 30.06.2024 तक रु. 64,98,290.28 (रु. बीस लाख निग्यान्वे हजार दो सौ नब्बे और अड़सह सौ मात्र) और ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और वसु इत्यादि सहित।

2. जकार्वा शाखा, उपकरणों का नाम - (1) श्री राकेश सिंह पति श्री विवेक सिंह, द्वितीय तल, गायन नगर, ओ/ओ श्री विद्या, माधुरी महाला, ग्नी पीठ हाउस और इंडसट्रियल पार्क एस्टेट के पास, वीरवार सेक्टर 52, सुदाम-122003 और प्लॉट नं. 137, 137बी नॉर्थ, टावर नंबर डी-4, सेक्टर 24, अवलौली हार्टडर, ग्नी अलवरपुर, धाकंडवा, रेवाड़ी हरियाणा-123110 (2) श्री संदीप मंगू पुत्र श्री राम मेहर मंगू, एफडीआर नंबर, मंडी रोड, सुदामपुर महाला, नई दिल्ली-110003 और कुल देय. दिनांक 30.06.2024 तक रु. 36,82,994.56 (रु. छत्तीस लाख अठारसी हजार नौ सौ बीसवाँ और पैसे अठ्ठान सौ मात्र) और ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और वसु इत्यादि सहित।

बैंक का प्रति: 1. रिहायशी भूखि एवं खन, जॉबि मुनिनीयन नं. एल-2/28, पूसा रोड प्लॉट नं. 28, सूर्य प्रभम ताल, शाही नगर, दिल्ली-110052 में स्थित, क्षेत्रफल 82 वर्ग मीटर, वह सम्पत्ति श्रीमती राज बाबा के नाम पर है। चौकटी उत्तर में - अन्य संपत्ति, दक्षिण में - अन्य संपत्ति, पूर्व में - रोड 20 फीट, पश्चिम में - संपत्ति से एल-2/28 का हिस्सा।

आवधिक मूल्य: ₹. 60,00,000/- ईसपीटी: ₹. 6,00,000/-

2. रिहायशी प्लॉट नं. 137, 137बी नॉर्थ, टावर नं. डी-4, सेक्टर 24, अवलौली हार्टडर, ग्नी अलवरपुर, धाकंडवा, रेवाड़ी हरियाणा - 123110 प्रकृत 1223 वर्ग फीट, चौकटी उत्तर में - अपार्टमेंट नं. डी-4/136, दक्षिण में - पार्क फेज, पूर्व में - अपार्टमेंट नं. डी-4/35, पश्चिम में - पार्क फेज।

आवधिक मूल्य: ₹. 28,35,000/- ईसपीटी: ₹. 3,00,000/-

**संपत्ति का निरीक्षण**

ऑनलाइन निविदा और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय

ई-नीलाामी की तिथि और समय

नोटिस बैंक खाते का नाम

संपर्क व्यक्ति एवं फोन नं.

सभी कार्यादेश: 01.08.2024 से 04.09.2024 को सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच

दिनांक: 05.09.2024

समय: शाम 5 बजे तक

ई-नीलाामी प्लॉट के माध्यम से 06.09.2024 को सुबह 11.00 बजे से 11.30 बजे तक 5 मिनट के अवधिमा विस्तार के साथ बिक्री समाप्त होगी तक

उपरोक्त खाता कर वेंचर बैंक लिमिटेड, केंद्रीय कार्यालय के पास में, खाता सं. 1101351000000973, आईएफएससी कोड: KVBIL0001101

उपरोक्त उपरिस्थित है।

हस्ता/— कर वेंचर बैंक लि. मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 01.08.2024.

## वीडा लाएगा नोएडा एयरपोर्ट के पास यमुना सिटी में घर बसाने को 2500 छोटे-बड़े प्लॉट की योजना

नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नवरात्रि में घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने का एक और मौका मिलेगा। लोगों की मांग को देखते हुए यमुना प्राधिकरण 2500 प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी में है। इनमें छोटे और बड़े प्लॉट होंगे। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि आवासीय सेक्टर में नए प्लॉट की योजना लाने की तैयारी है। सभी प्लॉट एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास हैं। एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के नजदीक आवासीय भूखंड योजना को लेकर लोग काफी समय से मांग उठा रहे थे। दिसंबर में एयरपोर्ट से उड़ान भी शुरू हो जाएगी, इसके अलावा फिल्म सिटी का निर्माण भी छह माह के अंदर शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्राधिकरण अक्टूबर में नवरात्रि पर 2500 प्लॉटों पर नई स्क्रीम शुरू करने की योजना बना रहा है। योजना में 90 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक के प्लॉट होंगे। इस स्क्रीम में भी पेंमेंट करने के तीन विकल्प होंगे। प्राधिकरण की आवासीय सेक्टरों में एक साल में दूसरी प्लॉट स्क्रीम होगी। प्राधिकरण आवंटियों को सुविधाओं को देने का काम कर रहा है।

**PUBLIC NOTICE**

**Paramjeet Kaur**  
EMP Code : 1012297, a nurse by profession, has worked in many hospitals for 13 years. Currently, she is working as the medical room in charge at Delhi Public School, Ghaziabad, and lives in Shailam Garden, Ghaziabad. While traveling, she saw Naresh Kumar (also known as Pankaj), a 59-year-old man who was with his wife. Suddenly, he fainted and fell down. People checked the old man and said he was dead. She checked the old man and started giving CPR. After repeating it 2-3 times, the old man's pulse rate came back, and he started breathing. Then he was taken to the nearby GTB Hospital, where his life was saved.

**PUBLIC NOTICE**

Re: Residential Dwelling Flat/Unit No. 1781, having its super area measuring 1290 sq. ft. (119.84 sq. mtrs.) on 17/F, Tower-Betina, situated in Complex known as Mahagun Modern, constructed under G.O. No. 22-11/2019 (SRO Notified). After the death of the said property, the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property, and subsequently mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta Arora, wife of the said property. In this connection, she has informed that the said property was owned by Mr. Under Kumar Sharma vide Transfer Form Sale Deed executed by Mrs. Bhawna Malik and Mr. Abhishek Malik in his favour. The said Deed is registered as Document No. 7595, Regd.No.1, Volume No.10957, pages 169-200, on 22-11-2019 (SRO Notified). After the death of the said property was mortgaged to the said property in favour of IDFC FIRST Bank Limited by our clientless, Mrs. Shikanta

# कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाएंगे : आतिशी

## जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस पर लगाम, भ्रामक विज्ञापन समेत कई बिंदुओं को रेगुलेट करेगी सरकार

● शिक्षा मंत्री ने कहा, देशभर में फैली कोचिंग इंस्टीट्यूटों को रेगुलेट करने के लिए अबतक कोई केंद्रीय कानून नहीं बना

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राजज आईएसएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के बाद दिल्ली सरकार जागी है। राष्ट्रीय राजधानी में नियमों को ताक कर कोचिंग संस्थानों की गैर कानूनी गतिविधियों और मनमानी पर नकेल कसने के दिल्ली सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। नए कानून के तहत कोचिंग संस्थानों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मनमाने फीस पर लगाम, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, शिक्षकों की योग्यता सहित तमाम जरूरी बिंदुओं को रेगुलेट करेगी सरकार। दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि देशभर में फैली कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसने के लिए अब तक कोई केंद्रीय कानून नहीं बना है। उनकी सरकार को कानून बनाने का इंतजार नहीं करेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट के जरिए दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के अनियमितताओं पर रोक लगायेगी। आतिशी और महापौर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को संवाददाता



राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंची दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और महापौर शैली ओबेरॉय। फोटो: रंजन डिमरी

सम्मेलन में कहा कि कानून बनाने के लिए सरकार कमिटी गठित करेगी। इसमें दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारियों समेत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के छात्र भी हिस्सा होंगे। सरकार ने इसके लिए ईमेल एड्रेस coaching.law.feedback@gmail.com भी जारी किया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली के लोगों और छात्रों से इसका अपना फीडबैक देने की अपील की है। इस बाबत दिल्ली सचिवालय में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यूपीएससी अभ्यर्थियों के साथ चर्चा की गई और उनके सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि, जाँच संबंधित बाकी रिपोर्ट 7 दिनों में

### राजेंद्र नगर में छात्रों से मिली शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री आतिशी बुधवार को राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी अभ्यर्थियों से मिली और उन्हें सरकार की ओर से सभी जरूरी सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वह छात्रों के साथ खड़ी हैं और उनकी बेहतरी व सुरक्षा में कोई समझौता बर्दाश नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री छात्रों से उनकी समस्या और मांगों को सुना और वादा किया वर्तमान में तुरंत एक्शन लेते हुए एमसीडी के जूनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया और असिस्टेंट इंजीनियर को सरपेंड कर दिया गया है। घटना की जाँच पूरी होते ही जिम्मेदार हर अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आएगी लेकिन अंतरिम जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले यहाँ ड्रेन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की गई और नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर को तुरंत सरपेंड कर दिया गया। क्योंकि फोल्ड ऑफिसर के रूप के उनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ

### सुरक्षा गाइडलाइंस लाए सरकार : सचदेवा

● कोचिंग सेंट्रों एवं पीजी के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस की मांग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा है दिल्ली सरकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाने की घोषणा महज एक छलावा है।

दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने प्रेस वार्ता का संचालन करते हुए कहा कि यह खेदपूर्ण है कि केजरीवाल सरकार आवश्यक गाइडलाइंस ला कर कोचिंग इंस्टीट्यूट समस्या का फौरी समाधान करने के बजाए सुझाव मांगने के खेल में और समाधान प्रक्रिया को इवेंट बनाने में लग गई है। सचदेवा ने कहा की दस साल पूर्व था यह एक्ट उतना ही आवश्यक था जितना आज है और इसी के साथ



दिल्ली को पीजी रेगुलेशन एक्ट की भी उतनी ही जरूरत है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। अन्य राज्यों से पढ़ने के लिए दिल्ली आने वाले छात्र उतने ही असुरक्षित वातावरण में रहने को भी बाध्य हैं जैसे में पढ़ने को। जलबोर्ड द्वारा की सौकर सफाई ना होना हो, फायर सर्विस द्वारा बिना बेसमेंट का वास्तविक उपयोग जांचे राव इंस्टीट्यूट भवन को एन.ओ.सी. देना हो, नगर निगम की नालियों पर अतिक्रमण रोकने की विफलता हो, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेसिक स्वास्थ्य निरीक्षण न करना हो सबके लिए आप शासित दिल्ली सरकार एवं नगर निगम हैं।

मौजूदा ड्रेन की जाँच की जाए और देखा जाए कि वो काम कर रहा है या नहीं। आतिशी ने कहा कि, वह दिल्ली और देश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही जाँच पूरी होगी तब इन अधिकारियों के अलावा और भी कोई अधिकारी जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसे भी बख्शा नहीं जायेगा और उसके

खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा अभी तक 35 बेसमेंट सील किए गए हैं लेकिन ये अल्पकालीन उपाय है। उन्हें उम्मीद थी कि, केंद्र देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी लेकिन अफसोस है कि केंद्र ने कोई कानून नहीं बनाया है।

# हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर में अभ्यर्थियों की मौत पर प्राधिकारियों को फटकारा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भरने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में प्राधिकारियों को बुधवार को फटकारा और कहा कि जब गंभीर संस्कृति के कारण कर संग्रह नहीं होता है, तब ऐसी त्रासदियाँ होना स्वाभाविक है। उच्च न्यायालय ने किसी केंद्रीय एजेंसी को घटना की जाँच का निर्देश देने का संकेत दिया और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त और मामले के जांच अधिकारी को शुक्रवार अदालत के समक्ष पेश होने को कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार एक गैरला की पीठ ने कहा कि एक अजीब जांच चल रही है, जिसमें

● अदालत ने कहा- जब रेवेडी संस्कृति के कारण कर संग्रह नहीं होता है तब ऐसी त्रासदियाँ होना स्वाभाविक

दिल्ली पुलिस ने ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बाहर से गुजरने वाले कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीठ ने कहा, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, इसके अधिकारी क्या कर रहे हैं, लीपापोती की कोशिश हो रही है क्या, क्या अब तक इस घटना के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपसे कह रहे हैं कि

एक बार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई, तो भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में नालों पर सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को शुक्रवार तक हटाने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा, यह बहुत ही गंभीर घटना है। शहर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की विफलता है। जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल अराजक है। हमें लगता ही नहीं है कि नगरीय एजेंसियाँ जमीनी स्तर पर काम भी करती हैं। बहुमंजिला इमारतों को संचालित करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन पानी की उचित निकासी की व्यवस्था नहीं है। आपके विभाग दिवालिया हैं। यदि आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप बुनियादी ढांचे को कैसे उन्नत करेंगे।

‘कोचिंग रेगुलेशन एक्ट गुमराह करना वाला’ नई दिल्ली। राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने के बाद डूब कर मरने वाले छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। यादव बादली विधानसभा के ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा व आम आदमी पार्टी छात्रों को न्याय दिलाने के जगह उनकी मौत पर राजनीति कर रही है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि जांच के नाम पर गुहमंत्रालय ने कमेटी गठित करके और मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा करके लीपापोती की है और पुलिस ने थार कार चालक को गिरफ्तार करके दोष ढूँढ़ने की पटकथा तैयार की है।

● अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने राजेंद्र नगर हादसे में विफलता को किया स्वीकार

सर्किल के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की चिंताओं पर कहा, जैसा कि आपने कहा, हमारे सामने ढांचगत मुद्दे हैं और उन्हें व्यवस्थित तरीके से हल करने की जरूरत है, यही मेरा समाधान है। उन्होंने एक छात्र की शिकायत का जवाब देते हुए कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि यह हम सबकी और व्यक्तिगत रूप से मेरी विफलता है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है, यह अधिकारियों के रूप में हमारी विफलता है।

### ‘कोचिंग रेगुलेशन एक्ट गुमराह करना वाला’

नई दिल्ली। राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने के बाद डूब कर मरने वाले छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। यादव बादली विधानसभा के ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा व आम आदमी पार्टी छात्रों को न्याय दिलाने के जगह उनकी मौत पर राजनीति कर रही है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि जांच के नाम पर गुहमंत्रालय ने कमेटी गठित करके और मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा करके लीपापोती की है और पुलिस ने थार कार चालक को गिरफ्तार करके दोष ढूँढ़ने की पटकथा तैयार की है।

# एमसीडी आयुक्त से मिलकर छात्रों ने जताई चिंता

● कई कोचिंग सेंट्रों में खराब सुरक्षा उपायों के बारे में की चर्चा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में एक कोचिंग सेंटर में हुई मौतों के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच सिविल सेवा अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को यहाँ एमसीडी मुख्यालय में एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार से मुलाकात की। छात्रों ने कुमार के साथ कई कोचिंग सेंट्रों में खराब सुरक्षा उपायों के कारण जीवन के खतरे एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक जारी है। इस बीच 27 जुलाई की घटना के खिलाफ मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सेवा अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को चौथे दिन भी जारी

### लाइसेंस प्राप्त पुस्तकालयों ने शुल्क किया दोगुना

सिविल सेवा अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि इमारत के बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कार्रवाई के बाद यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर और इसके आसपास के इलाकों में लाइसेंस प्राप्त पुस्तकालयों ने अपना शुल्क दोगुना कर दिया है। एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर में उन इमारतों पर कार्रवाई की है, जो बेसमेंट का इस्तेमाल पुस्तकालयों समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। नगर निगम ने यह कार्रवाई पिछले शनिवार को भारी बारिश के बाद इलाके के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित लाइब्रेरी में पानी भर जाने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के बाद की थी।

रहा। इस घटना में तीन अभ्यर्थियों की जान चली गई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदर्शन की भावी रणनीति तय करने और संबंधित अधिकारियों से संवाद करने के लिए 15 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की गई है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र गौतम ने कहा, हमने 15 सदस्यीय वाली एक समिति गठित की है और समिति के सदस्य आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेंगे। विभिन्न कोचिंग सेंट्रों के

अभ्यर्थी रविवार से राजज स्टडी सेंटर के सामने धरना दे रहे हैं। कुछ छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। एक छात्र सुनील कुमार ने कहा, जबतक हमारी मांगें मान नहीं ली जाती हैं तबतक आंदोलन जारी रखेंगे। पुलिस उपायुक्त (मध्य) एम. हर्षवर्धन ने बताया कि बरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शन स्थल का दौरा कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगें समझने की कोशिश कर रहे हैं।

# नाले से गाद निकालने पर ऑडिट रिपोर्ट तलब

● दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को जारी किए आदेश

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे नालों से गाद निकालने के काम में शामिल ठेकेदारों को तब तक भुगतान न करें, जब तक उनके काम का तीसरे पक्ष से ऑडिट पूरा नहीं हो जाता। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में नाले का पानी एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में संचालित

### निगम ने दिल्ली वालों को किया निराश : भाजपा

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि भ्रष्टाचार और अरिबिंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली की सीवरेज प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बुधवार शाम हुई भारी बारिश से फिर पूरे शहर में जलभराव हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में बारिश से जलजमाव के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी को सीवर साफ करने के लिए बंधास समय दिया, लेकिन उन्होंने आज फिर से दिल्ली वासियों, विशेष रूप से पुराने राजेंद्र नगर के निवासियों को निराश किया। शर्मनाक बात यह है कि वह स्थान जहाँ मंत्री आतिशी और महापौर शैली ओबेरॉय ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की, कुछ मिनट की बारिश में ही कमर तक पानी में डूब गया।

पुस्तकालयों में भर जाने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मद्देनजर उदाया गया है।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के पत्र के जवाब में, मुख्य सचिव ने कहा कि अतिरिक्त

मुख्य सचिव (शहरी विकास) को विभिन्न एजेंसियों द्वारा नालों से गाद निकालने के काम के तीसरे पक्ष से ऑडिट पर मंत्री द्वारा मांगी गई जानकारी के साथ एक तथ्यात्मक नोट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

# निजी-सरकारी स्कूलों के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश

● बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ तय नियमों के अनुसार किया जाए : शिक्षा निदेशालय

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजेंद्र नगर हादसे के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट की सिविलिटी और सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निजी और सरकारी स्कूलों को सार्वजनिक भवनों में बेसमेंट के उपयोग के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के प्रावधानों का पालन करना होगा। स्कूल प्रशासन को स्कूल परिसर में और उसके आसपास जलभराव से बचने के लिए अपने स्तर पर सभी आवश्यक कदम सुनिश्चित करने होंगे। शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दिल्ली में

हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें तीन सिविल सेवा उम्मीदवार एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में डूब गए और एक उम्मीदवार की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। ऐसे में यह जरूरी है कि सभी स्कूल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उचित आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करें। स्कूल भवनों के सभी द्वार चालू होने चाहिए और प्रवेश और निकास के लिए खुले होने चाहिए। बेसमेंट तक पहुंच को स्कूल निकासी योजना में उचित रूप से चिह्नित और स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। सभी गलियारों पर समय अवरोधों से मुक्त होने चाहिए और सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल के गलियारों और सीढ़ियों की नियमित रूप से पानी के जमाव के लिए जाँच की जानी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। अप्रिय घटना से बचने के लिए तारों और फिटिंग, उपकरणों की जाँच की जानी चाहिए।

### आवासीय इमारत में लगी आग, 10 को बचाया गया

नई दिल्ली। कीर्तिनगर स्थित एक आवासीय इमारत में बुधवार को आग लगने के बाद 10 लोगों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। डीएफएस के एक बरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सुबह आठ बजे कर 40 मिनट पर एक घर में आग लगने के संबंध में फोन से सूचना मिली। दो दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि आग ने कुछ बिजली मीटर, बिजली पैनेल बोर्ड और दो स्कूटर्स को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने कहा, हमारे अधिकारियों ने अलग-अलग मंजिलों से 10 लोगों को सुरक्षित बचाया। तीन मंजिल मकान में भूमितल पार्किंग भी है।

# सांक्षिप्त समाचार



हरिद्वार से कांवड़ लेकर आता हुआ कांवड़िया।

### रोडरेज में महिला की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके के फ्लाईओवर के रोडरोज में बाइक से जा रही महिला की हत्या कर दी गई। घटना के समय महिला पति और बच्चों के साथ कहीं जा रही थी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर बदनमशीनों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिमरनजीत कौर अपने पति हीर सिंह और बच्चों के साथ भलवासी रोड की गुरु नानक कलोनी में रहती थी। बुधवार को करीब सवा तीन बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कूटी सवार ने बुलेट पर जा रही महिला पर गोलीयाँ चलाई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सिमरनजीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय हीरा सिंह, पत्नी और दो बच्चों के साथ दुर्गापुरी चौक स्थित बैंक में काम से जा रहे थे। गोकलपुरी फ्लाई ओवर के पास हीरा सिंह की बुलेट एक स्कूटी सवार से टकरा गयी जिसके बाद गुस्ताए स्कूटी सवार ने गोली चला दी, सिमरनजीत की गर्दन के पास दो गोलीयाँ लगी।

### मानसून में भी यमुना जहरीली : बिधुडी

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधुडी ने मानसून में भी यमुना में भयंकर प्रदूषण पाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही और अनेकियों के कारण राजधानी में यमुना दम तोड़ चुकी है। जुलाई में यमुना में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य पाई गई है जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को 8500 करोड़ रुपए दिए लेकिन कोई हिसाब-किताब ही नहीं है।

### स्वतंत्र जांच की मांग को राष्ट्रपति को लिखा पत्र

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के एक समूह ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे एक कोचिंग सेंटर के इमारत के पानी भर बेसमेंट में हुई तीन विद्यार्थियों की मौत की स्वतंत्र जांच करने का अनुरोध किया है।

# आटा गुथने की मशीन की चपेट में आने से नाबालिग की मौत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

बेमगपुर इलाके में आटा गुथने वाली मशीन की चपेट में आने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गयी। मृतका इलाके नवीन विहार में एक मोमोज, फ्रिज रोल, सोया चाप बनाने वाली दुकान पर काम करती थी। मंगलवार को रोजाना की तरह नाबालिग घर से काम पर आई थीं जेरा शाक को दुकान मालिक ने परिजनों को फोन पर बताया उनकी बेटी मशीन में फंस गयी है। आनन-फानन में परिवार वाले जब दुकान पहुंचे तो देखा कि लड़की का ऊपरी हिस्सा मशीन में फंसा हुआ था। मामले को जानकारी पुलिस को देने के बाद

पुलिस ने नाबालिग को मशीन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम करीब सवा 7 बजे जानकारी मिली कि नवीन विहार, हनुमान चौक के पास एक लड़की मशीन में फंस गयी है पुलिस ने नाबालिग को अस्पताल पहुंचाया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजेश कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। परिजनों के अनुसार हादसे के समय नाबालिग मोमोज के लिए आटा गुंथ रही थी। अलावक मशीन की चपेट में आने से उसका ऊपरी हिस्सा मशीन में फंस गया था।

# एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी एसी ई-बसें

● पास के मेट्रो स्टेशनों और बस स्टॉप से एक्स परिसर के विभागों तक पहुंच होगी आसान

संजय राय। नई दिल्ली

देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उत्तर भारत समेत अन्य राज्यों के मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में मरीजों को एक विभाग से दूसरे विभाग में आने-जाने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का सहारा लेते हैं। हालांकि एम्स प्रशासन ने मरीजों और तीमारदारों को परिसर में कई तरह की



फाइल फोटो

सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं लेकिन यहां आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए ये सुविधाएं बहुत की कम हैं। वहीं डॉक्टर को दिखाने के बाद मरीजों को बस स्टैंड और मेट्रो

स्टेशनों तक जाने में भी दिक्कत होती है। अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एम्स जल्दी ही 20 सीटों वाली एसी ई-बसें को बुधवार मरीज और उनके तीमारदारों के लिए

### इन मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप से मिलेगी बस

रीमा दादा ने बताया कि एसी बस की सुविधा एम्स के नजदीकी मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर, साउथ एक्स, ग्रीन पार्क आदि मेट्रो स्टेशनों से शुरू की जाएगी। इसके अलावा नजदीकी बस स्टॉप किदवई नगर, गौतम नगर और भीकाजी कामा प्लेस से सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि एम्स के निदेशक प्रो. एम. श्रीनिवास के नेतृत्व में तैयार की गई यह एक समग्र योजना सार्वजनिक परिवहन द्वारा संस्थान के भीतर आंतरिक स्थलों तक कनेक्टिविटी को सुलभ बनाएगी। ये 20 सीटर ई बसें आधुनिक सुविधाओं एयर-कंडीशनिंग, लो प्लतार और व्हीलचेयर की सुविधा से लैस होंगी।

शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें एम्स तक पहुंचने के लिए महंगे ऑटो, ई रिक्शा से निजात दिलाई जा सके। एम्स मीडिया सेल की इंचार्ज प्रोफेसर रीमा दादा ने बताया कि संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास की पहल से शुरू की जाएगी। ताकि देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप से एम्स आने में होने वाली

परेशानियों को देखते हुए की गई है। एसी बस की सुविधा शुरू होने के बाद मरीज और उनके तीमारदारों को कम किराए में मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप से ही एम्स के अंदर तक इलेक्ट्रिक एसी बस की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कि यहां तक पहुंचने में उनके समय और पैसे की भी बचत होगी। ई-बस सेवा की मुख्य विशेषताएं : बेहतर कनेक्टिविटी

और सेवाओं से मरीजों को निजी परिवहन का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त होगी। इससे लोग निजी वाहनों का उपयोग कम करेंगे और बसें से ही एम्स के अंदर तक कमी आएगी। नियमित सेवा पीक ऑवर्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के दौरान हर 10 और 15 मिनट में उपलब्ध होगी। मरीजों के लिए शेटलर की जानकारी देने के लिए कॉल बटन की सुविधा भी होगी।

# देश के विकास में सिखों का बड़ा योगदान: मनोहर

## सिख समाज की ओर से आयोजित किए अपने सम्मान समारोह में बोले केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों मंत्री

● झंझर से मनु  
भाकर और अंबाला से  
सरबजोत सिंह को मेडल  
जीतने पर दी बधाई

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

केन्द्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी मामलों मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिख समाज का देश के विकास में हर क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान रहा है। देश की अर्थ व्यवस्था और रक्षा में तैनात सेना बल में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सिख समाज से आह्वान करते हुए कहा कि देश-प्रदेश की तरक्की व विकास में इसी प्रकार से सिख समाज के लोग लगातार हर क्षेत्र में भाग लेते हुए आगे बढ़ाने का काम करते रहें।

मनोहर लाल नई दिल्ली में बेल-ला-मोंटे रिशार्ट में उनके सम्मान में रखे गए एक प्रीतिभोज कार्यक्रम में हरियाणाभर से पहुंचे सिख समाज के



अपने सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में पूरे हरियाणा से पहुंचे सिख समाज के उद्योगपतियों से मिलते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल।

उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के ओएसडी डॉ. प्रभलीन सिंह भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री ने अपने आपको सिख समाज का हिस्सा बताते हुए कहा कि सिख समाज का हर क्षेत्र में योगदान रहा है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि आज हरियाणा के दो

खिलाड़ियों झंझर से मनु भाकर और अंबाला से सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश-प्रदेश का नाम रोशन किया है। मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में सिख समाज के प्रति बहुत सम्मान है।

स्वागत करते हुए कहा कि सिखों को देश के विकास में अहम भूमिका हमेशा से रही है। इस अवसर पर बेलमोंडे ग्रुप के चेयरमैन डॉ. गुरमीत सिंह, पूर्व कुलपति पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला डॉ. जसपाल सिंह, सिम्मा ग्रुप के डॉ. जगदीप सिंह चड्ढा, जमुना ऑटोस के रणबीर सिंह जोहर, विकटोरा ग्रुप के सरदार

### मैंने केवल तीन दिन के भीतर सीएम की कुर्सी छोड़ी

मनोहर लाल ने राजनीति के संबंध में बात करते हुए कहा कि राजनीति में कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने 11 मार्च से 13 के बीच, केवल तीन दिनों के भीतर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि उनको केन्द्र में जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि आज मैं केन्द्र में मंत्री हूँ। करनाल की जनता ने उन्हें जिलाकर लोकसभा में भेजा है। उनके मेरे पास दो बड़े ही अहम बिजली और आवास विभाग हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में देशभर के लोगों की जो भी अपेक्षाएँ हैं। उस संबंध में उनके द्वारा कार्य किया जाएगा।

सरिंदर सिंह बंगा, वीजॉन ग्रुप के सरदार हर्षित सिंह कोचर के अलावा हरियाणा के सभी सिख उद्योगपति और व्यवसायी मौजूद रहे।

# ट्रक की टक्कर लगने से कांवड़िये की मौत

● गुस्साए कांवड़ियों ने दिल्ली-जयपुर हाइवे किया जाम

● मृतक के परिजनों के लिए मांगा 50 लाख का मुआवजा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

यहां दिल्ली-जयपुर एनएच-48 पर रामपुर फ्लाईओवर के पास हादसे में एक कांवड़िये की मौत हो गई। यह घटना सुबह पाँचे 3 बजे हुई। घटना से गुस्साए कांवड़ियों ने हाइवे पर जाम लगा दिया। सुबह 6 बजे के बाद यह जाम खुल पाया।

जानकारी के अनुसार मंगलवार-बुधवार की सुबह एक डाक कांवड़ राजस्थान के कोटपुतली ले जायी जा रही थी। शिव भक्त भोले शंकर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच एक तेज रफ्तार ट्रक ने डाक कांवड़ में शामिल एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 17 साल के एक कांवड़िये की मौत हो गई और

### आरोपी चालक काबू

बुधवार की सुबह रामपुर फ्लाईओवर के पास कांवड़िये की बाइक में टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खेड़कीदौला पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त मानेसर दीपक के मुताबिक इस हादसे के आरोपी को थाना खेड़कीदौला क्षेत्र से काबू किया गया है। आरोपी ट्रक चालक की पहचान कुलदीप निवासी गांव बंदसहापुरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

दो अन्य युवक घायल हो गए। इस हादसे के बाद कांवड़ियों ने हाइवे को जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसपी, डीसीपी के अलावा एडीएम ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया। जनहित में हाइवे से जाम हटाने को कहा। तीन घंटे से भी अधिक समय तक कांवड़िये हाइवे को जाम किए रहे। अधिकारियों ने उनसे घंटों तक

### अवैध शराब सहित एक महिला गिरफ्तार

गुरुग्राम। अवैध शराब के आरोप में पुलिस ने एक महिला को काबू किया है। आरोपी महिला के पास से 55 पक्के अवैध शराब भी बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ राजेंद्र पार्क थाना में केस दर्ज किया गया है। थाना राजेंद्र पार्क पुलिस द्वारा मंजू देवी निवासी गली सूरत नगर फेज-2, उसी कालोनी से अवैध शराब सहित काबू किया। पुलिस ने महिला के कब्जे से 28 पक्के अंग्रेजी शराब व 27 पक्के देशी शराब बरामद की है।

अनुरोध किया, तब जाकर कांवड़ियों ने जाम खोला। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं इस हादसे में मारे गए कांवड़िये ने मांग की है कि हेमंत के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

# डॉ. नेहरू ने की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात

● स्टार्ट अप और उद्यमिता के प्रावधानों पर की चर्चा, विवि में आने का दिया निर्मंत्रण

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें स्टार्ट अप तथा उद्यमिता पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बजट में स्टार्ट अप पर किए गए प्रावधानों पर भी चर्चा की।

कुलपति डॉ. राज नेहरू ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्ट अप के क्षेत्र में की गई पहल और नीतियों से अवगत करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को विश्वविद्यालय परिसर के अवलोकन का निर्मंत्रण भी दिया। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में कौशल



केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत करते श्री विश्वकर्मा कौशल विवि के कुलपति डॉ. राज नेहरू।

शिक्षा का दोहरा मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हालिया बजट से पूर्व भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौशल संबंधित प्रावधानों पर परामर्श के लिए कुलपति डॉ. राज नेहरू को विशेष तौर पर आमंत्रित किया था। डॉ. राज नेहरू ने बताया

कि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ एक सार्थक मुलाकात हुई। उन्हें स्टार्ट अप को लेकर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए इको सिस्टम की जानकारी दी और केंद्रीय बजट में स्टार्ट अप को लेकर किए गए प्रावधानों पर भी चर्चा की।

# एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एनएचआई व पुलिस ने लगाए पौधे

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण में सुधार के लिए एक पेड़ मां के नाम के अभियान में हर कोई हिस्सा ले रहा है। पुलिस भी इससे पीछे नहीं है। पुलिस जगह-जगह पर पेड़ लगाने का अभियान चला रही है।

पुलिस उपायुक्त सिद्धांत जैन के आदेशानुसार प्रबंधक थाना भोंडसी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एनएचआई के साथ मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के दोनों तरफ पौधारोपण किया गया। इस दौरान लगभग 500 पौधे लगाए गए। पुलिस उपायुक्त सिद्धांत जैन के अनुसार वातावरण को शुद्ध, हरा भरा रखने के लिए वारिश के इस मौसम में गुरुग्राम पुलिस द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। इस पौधारोपण अभियान में पुलिस



भोंडसी थाना क्षेत्र में पेड़ लगाते पुलिसकर्मी।

कर्मचारियों तथा आमजन द्वारा भी बड़-चढ़ रू भाग लिया जा रहा है। मानसून के दौरान पौधे लगाने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गुरुग्राम पुलिस सभी से अपील भी करती है कि अपने आस-पास अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाकर उनकी देखभाल करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।

# तीन दिवसीय खेल महाकुंभ आज से, 2433 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

● केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह होंगे मुख्य अतिथि, हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह होंगे विशिष्ट अतिथि

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुवार को सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के खेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। सोहना के एसडीएम

व आयोजन के नोडल अधिकारी सोनू भट्ट ने बताया कि खेल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत राज्य जिला में 1 से 3 अगस्त के बीच तीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

तीन दिवसीय खेल महाकुंभ में गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आर्चरी व एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन सोहना के भोंडसी स्थित आरबीएसएम स्कूल में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजन में करीब 2433 खिलाड़ियों के पहुंचने की संभावना है। सोनू भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

## संक्षिप्त समाचार



आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल का आभार व्यक्त करती नवनियुक्त महिला जिला अध्यक्ष व उनकी टीम।

### रेखा भसीन का महिलाओं ने किया स्वागत

गुरुग्राम। रेखा भसीन को आम आदमी पार्टी की गुरुग्राम की महिला शाखा की जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर महिलाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तथा नवनियुक्त हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेखा भसीन के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की गुरुग्राम में मजबूती मिलेगी। महिला शाखा की जिलाध्यक्ष रेखा भसीन ने उमेश अग्रवाल एवं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वह उस पर खरा उतरेंगी। गुरुग्राम के प्रत्येक घर तक आम आदमी पार्टी को जोड़ने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि आप पार्टी जन मानस के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। महिलाओं ने पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल के कार्यालय पर ही आगामी 7 अगस्त को हुडा मैदान सेक्टर-5 में आयोजित होने वाले भव्य तीज महोत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में एक बैठक आयोजित की। जिसमें अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की जिलाध्यक्ष मीनाक्षी गुप्ता ने बताया कि इस बार का तीज महोत्सव ऐतिहासिक होने के साथ-साथ स्मरणीय भी रहेगा। इस बैठक में जिलाध्यक्ष मीनाक्षी गुप्ता के साथ-साथ इंदु जैन, अनुराधा शर्मा, रेखा भसीन, अंजलि राही, पूजा, बाला, विभूति गुप्ता, दया गुप्ता, रेनु गुप्ता, हेमा अग्रवाल, हेमा शर्मा, क्षमा गर्ग, स्वाति गुप्ता, मेधा गुप्ता, संतोष कवात्रा, पूजा गांधी, मीनाक्षी गुप्ता, सविता अग्रवाल, मधु गुप्ता, डौली गुप्ता, शालिनी गुप्ता एवं रेनु आहूजा मौजूद थे।

### नकदी, आभूषण व मोबाइल चोरी कर ले गया नौकर

गुरुग्राम। बादशहपुर थाना के अंतर्गत एक मकान से चोरी करने के आरोपी नौकर को पुलिस ने काबू किया है। गृह स्वामी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, गृह स्वामी ने उन्हें शिकायत देकर कहा है कि 27-28 जुलाई की रात को ट्यूबलैट वायलेट सेक्टर-69 से उसका नौकर आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन व कार चोरी कर ले गया। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके तलाश शुरू की। अपराध शाखा सिकंदरपुर ने आरोपी नाबालिग नौकर को रोजका मेव नूह से काबू किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की हुई कार बरामद कर ली है।

### पटौदी में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा 11 अगस्त को गुरुग्राम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखबीर तंवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षीय कुशासन के कफन में कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा अंतिम काल साबित होगी। बुधवार को यहां जारी बयान में सुखबीर तंवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की विफलता का लंबी फेहरिस्त है। हरियाणा प्रदेश में तथाकथित डबल इंजन लोकसभा चुनाव में टूट चुका है। सरकार की ओर से हजारों स्कूल मर्जर के नाम पर बंद करना शिक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा है। स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचागत विकास नहीं हुआ, गुरुग्राम की आबादी में निरंतर बेहताशा वृद्धि और प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाले जिला के सिविल अस्पताल में विगत 10 वर्षों में एक भी ईंट नहीं लगाकर उसको पार्किंग स्थल बना देना सरकार के अत्यंत घटिया प्रदर्शन की बानगी है। प्रदेश बेरोजगारी में प्रथम स्थान और 75 प्रतिशत आरक्षण कानून न्यायालय द्वारा रद्द होना, युवाशक्ति का नशे और अपराध में अग्रसर होना भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की विफलता के प्रत्यक्ष प्रमाण है।

# भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच निगम ने दी सफाई

● कहा, 58701 मीट्रिक टन कचरा बंधवाड़ी प्लांट पहुंचाने का काम किया

● एजेंसियों को निर्धारित दरों पर 22 करोड़, 89 लाख, 3 हजार, 390 रुपए का किया जाना है गुगतान

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

नगर निगम की ओर से अपने अधिकार क्षेत्र में गंदगी उठाने में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच ऐसा कुछ भी होने से इंकार किया है। साथ ही कहा है कि स्वीप के तहत 58701 मीट्रिक टन कचरा उठाकर बंधवाड़ी



कचरा निस्तारण प्लांट में भिजवाया गया है। इसकी एवज में एजेंसियों को निर्धारित दरों पर 22 करोड़ 89 लाख 3 हजार 390 रुपए का भुगतान किया जाना है। नगर निगम की ओर से कहा गया है कि ठोस कचरा पर्यावरण आवश्यक्ता कार्यक्रम (स्वीप) के तहत नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया है। इसके तहत एक ओर जहां सड़कों, गलियों, ग्रीन बेंच, बाजारों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था

दुरुस्त की गई, वहीं दूसरी ओर गाबेंज वर्नेबल प्लांटों तथा सेकेंडरी कलेक्शन प्लांटों से कचरा उठाकर बंधवाड़ी स्थित कचरा निस्तारण प्लांट में भिजवाया गया।

नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (स्वच्छ भारत मिशन) निजेश कुमार के मुताबिक स्वीप के दौरान नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्लांटों से जुलाई माह में कुल 58701 मीट्रिक टन कचरा उठाकर बंधवाड़ी कचरा निस्तारण प्लांट में भिजवाया है। इसके लिए रूिच की अभिव्यक्ति समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करके एजेंसियों को आमंत्रित किया गया तथा पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए 390 रुपये प्रति टन की दर पर एजेंसियों को कचरा उठान का कार्य सौंपा गया। इन एजेंसियों ने सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्लांटों से कचरा उठाकर बंधवाड़ी कचरा निस्तारण प्लांट में पहुंचाया।

# खोखरा जोहड़ मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

वजीराबाद के खोखरा जोहड़ पांच मंजिला मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व हर्ष उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर समाजसेवी मयंक शर्मा परिवार द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई।

विद्वान ब्राह्मणों ने विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ का सवा सवा लाख मंत्रों का जाप किया जा रहा है। लगातार 8 दिन सवा सवा लाख मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मयंक शर्मा ने बताया कि 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक लगातार हवन यज्ञ किए जाएंगे। 2 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उसी दिन जलाभिषेक किया जाएगा। महाशिवरात्रि को शिवरात्रि के समय मंदिर परिसर में बहुत से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और शिवलिंग का भी भस्म अभिषेक किया जाएगा। इस अवसर



महाशिवरात्रि पर्व पर हवन यज्ञ करते सदस्य।

पर समाजसेवी मयंक परिवार की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जायेगा, जिसमें हजारों की संख्या में संत समाज व श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर पंडित इंद्रजीत शर्मा, विमल शर्मा, केशव शर्मा, परमजीत जून, वरुण धवन, गणेश, मुकेश यादव, हिमानी बरला, अलंकृता घोष, अदिति वशिष्ठ आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।

# मादक पदार्थ के साथ पकड़े विदेशी नागरिक सहित 2 लोगों को 5 व 12 साल की कैद

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए एक विदेशी नागरिक समेत दो आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 5 व 12 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार 26 मई 2019 को कुतुब प्लाजा मार्केट के पास से 1 विदेशी नागरिक को 345 ग्राम अफीम के साथ काबू किया था। उसका एक अन्य साथी पुलिस टीम को देखकर 4.285 किलो ग्राम नशीला/मादक पदार्थ फेंक कर भाग गया था। जिसको बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विदेशी नागरिक वैध वीजा व पासपोर्ट पुलिस के सामने पेश नहीं कर सका था।

अवैध अफीम व चरस बरामद किए जाने तथा विदेशी नागरिक के बिना वैध वीजा के पाए जाने पर आरोपी

युवकों के विरुद्ध थाना डीएलएफ फेज-1 में धारा एनडीपीएस एक्ट तथा फॉर्नर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपियों की पहचान पेंटिक डेजीविंस्की निवासी पोलैंड व काजी निवासी कुल्टू (हिमाचल-प्रदेश) के रूप में हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किया गया था। जिनके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को इस केस में दोषी करार दिया गया। विदेशी नागरिक को फॉर्नर एक्ट के तहत 4 वर्ष कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 वर्ष कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी को 12 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा तथा अन्य एक्ट में 12 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

# गोयल ने निगमायुक्त को बताई समस्याएं

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

शहर की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका निराकरण कराकर जनता को राहत दिलाने में जुटे व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा, हरियाणा के प्रमुख नवीन गोयल ने इस बार कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ से मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम समेत पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले करीब 10 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। गुरुग्राम का विकास बहुत ही अहम है। केंद्र व राज्य सरकार की



नगर निगम आयुक्त को मांग पत्र सौंपते नवीन गोयल व अन्य मौजिज लोग।

परियोजनाओं पर यहां लगातार काम चलता है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास में सरकार, आम आदमी की भी बड़ी भूमिका है। किसी को कोई पत्र में उन्होंने सफाई व्यवस्था को दुर्लक्ष करने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हम समस्याओं पर मिलकर काम कर सकते हैं।

# भारत में काम के अवसर बहुत, मगर स्किल की है कमी: कल्याण चक्रवर्ती

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

दुर्बई में बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी एमार के इंडिया कंट्री सीईओ कल्याण चक्रवर्ती का मानना है कि हमारे देश में काम के अवसर बहुत अधिक हैं। अगर कहीं कमी है तो यहां स्किल लेबर की है। इस कमी को दूर करके हम देश के अधिकाधिक युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। इस दिशा में एमार इंडिया निरंतर काम कर रहा है। यह बात उन्होंने बुधवार को गुरुग्राम स्थित एम्मार इंडिया कंपनी कार्यालय में विशेष बातचीत के दौरान कही।

कल्याण चक्रवर्ती ने कहा कि चाहे निर्माण क्षेत्र हो या तकनीक का कोई अन्य क्षेत्र, आज हर जगह प्रशिक्षित व स्किलड लेबर की जरूरत है। सुविधाएं दुरुस्त रखने में इनका अहम योगदान रहता है। अनस्टैंड या अनस्किलड लेबर को काम में लगाकर कालिटी बनाकर रखी नहीं की जा सकती। इसके लिए स्किलड लेबर होना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने ब्रांड को वैल्यूएबल बनाकर रख सकते हैं। ऐसे में एमार इंडिया ने अपने क्षेत्र में श्रम नामक कार्यक्रम को शुरूआत की है। इसके तहत स्किल पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी अपने

● काम में वालिटी देने के लिए स्किल को देना होगा बढ़ावा

● एमार इंडिया इस क्षेत्र में कर रही है काम

सीएसआर फंड से गरीब बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही है। किसी भी कंपनी की सीएसआर फंड समाज के हित में लगाना ही चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने बच्चों की शिक्षा को चुना है। उन्होंने कहा कि हम किसी को कुछ दान देना चाहते हैं



एमार इंडिया के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती।

तो उसे शिक्षा का दान दें, ताकि वह अपने जीवन में कामयाब हो सके। हमारे देश में लाखों बच्चे शिक्षा से

वंचित हैं। कुछ संसाधनों के अभाव से स्कूल छोड़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने फंड का सदुपयोग करते हुए गरीब बच्चों को स्कूल की दहलीज तक पहुंचाकर उन्हें समाज की लीज तक पहुंचाएं। हमारे देश में सीईओ कल्याण चक्रवर्ती ने कहा कि देशभर में आज तक 22 हजार से ज्यादा यूनिट्स एमार ने तैयार करके खरीदारों को हैंडओवर कर दी हैं। इसमें अकेले गुरुग्राम में करीब 13 हजार 500 यूनिट बेची गई हैं।

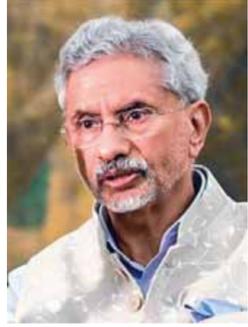
पुराने समय की ग्राहकों के जो भी शिकायतें या समस्याएं थीं, उन सभी को पूर्ण रूप से दुरुस्त करके सभी को उनकी प्रॉपर्टी दे दी गई हैं। उन्होंने एक साल के जवाब में कहा कि जिस तरह से बुर्ज खलीफा दुर्बई की पहचान है, भविष्य में एमार गुरुग्राम में भी ऐसा कुछ बनाएगा, जिससे कि गुरुग्राम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पहचान हो।



## भारत-चीन संबंध

### तनाव की स्थिति

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं, लेकिन इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं हैं। उनका हालिया बयान भारत और चीन के बीच वर्तमान समय में जारी राजनयिक तनाव रेखांकित करता है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका अर्थ था कि हमें चीन के खिलाफ काम करने के पहले दो बार सोचना चाहिए। विदेश मंत्री द्वारा वर्तमान समय में भारत-चीन संबंधों का आंकलन उन चुनौतियों को रेखांकित करता है जो विभिन्न राजनयिक प्रयासों तथा उच्चस्तरीय संपर्क के बावजूद बनी हुई हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान का एक प्रमुख तत्व यह था कि उन्होंने चीन के साथ विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की 'मध्यस्थता' से साफ इनकार किया। विदेश मंत्री ने जोर दिया कि भारत चीन के साथ अपने मुद्दे द्विपक्षीय स्तर पर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हल करना चाहता है। यह दृष्टिकोण भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रत्यक्ष प्रबंधन की दीर्घकालीन नीति का हिस्सा है। जयशंकर की टिप्पणी विदेश नीति में संप्रभुता व स्वायत्तता बनाए रखने के भारतीय दृष्टिकोण की परिचायक है। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार कर भारत चीन के साथ अपने मतभेद प्रत्यक्ष संवाद व बातचीत के माध्यम से हल करने के इरादे का संकेत दे रहा है। भारत का यह दृष्टिकोण स्थापित राजनयिक चैनलों के माध्यम से विवाद समाधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है। इससे वह विदेशी प्रभाव को अस्वीकार करता है जिससे प्रक्रिया में बाधा आ सकती है तथा वह और जटिल हो सकती है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान में दिलचस्पी दिखाई, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को भारत आमंत्रित कर उनका जोरदार स्वागत किया गया, पर इससे बर्फ नहीं पिघली और सीमाओं पर तनाव जारी रहा। भू-राजनीति की जटिलताओं में भारत अमेरिका के ज्यादा निकट आया है जो भारत का प्रयोग चीन का प्रभाव सीमित करने के लिए करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से चीन इससे बहुत चिंतित है। चीन की बेचैनी सीमा पर उसकी कार्रवाइयों से प्रकट होती है जो 1962 से 2017 में 'डोकलामा घटना' होने तक शांतिपूर्ण बनी रही। भारत-चीन संबंध जटिल और बहुआयामी हैं जिन पर ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक व रणनीतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। दोनों देशों के बीच काफी लंबी सीमा है। 1962 में अक्सईचिन क्षेत्र में सीमा विवाद के कारण भारत-चीन युद्ध हुआ था। मजबूत बात है कि सीमा विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़े हैं। चीन भारत का एक सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। लेकिन हालिया वर्षों में सीमा पर टकराव तथा रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है। हालिया वर्षों में संबंधों में सहयोग व टकराव, दोनों शामिल रहे हैं। 2017 में हुई डोकलाम झड़प सीमा पर तनाव का प्रमुख उदाहरण है। यह टकराव डोकलाम पठार पर हुआ जो चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है। 2020 में गलवान घाटी में झड़प से टकराव और बढ़ा। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भारत और चीन लगातार राजनयिक और आर्थिक संबंध बनाए रहे। दोनों देशों ने परस्पर लाभ के दृष्टिकोण से मतभेदों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता अनुभव की है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय भू-राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

# विकसित भारत हेतु संतुलित बजट

2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण को केन्द्रीय स्थान मिला है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, एसएमई को सहायता मिलेगी तथा निर्भरता घटाने के लिए खोज को गति मिलेगी।



के.एस. तोमर (लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण को बजट में केन्द्रीय स्थान मिला है। इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कृषि, विनिर्माण व तकनीक में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। बजट में घरेलू उत्पादन बढ़ाने, छोटे एवं मझोले उद्यमों-एसएमई की सहायता करने तथा खोज प्रोत्साहित करने पर जोर है। इन पहलों का उद्देश्य आयात निर्भरता घटाना तथा जीवन व टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही बजट में मोदी के वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत के संबंधों पर भी जोर दिया गया है। भारत की निर्यात प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई आकर्षित करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सहभागिता का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टिकोण से वैश्विक बाजार से संबंध मजबूत करने के साथ घरेलू क्षमताओं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यह संतुलित दृष्टिकोण भारत के लिए महत्वपूर्ण है जिससे वह लगातार जटिल होती वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में चुनौतियों का सामना कर अवसरों का लाभ उठा सकेगा।



सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पैसा एकत्र करने व नीतिगत क्रियान्वयन में भेदभाव का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि केन्द्रीय योजनाओं व पैसे के आबंटन में बजट प्लेगिंग योजनाओं, जैसे 'प्रधानमंत्री आवास योजना'-पीएमएवाई और 'आयुष्मान भारत' में 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव करता है। लेकिन विपक्षी राज्यों का तर्क है कि फंड आवश्यक्ताओं की अभिव्यक्ति नहीं करता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने दावा किया है कि पीएमएवाई में काफी आबंटन के बावजूद पैसा जारी करने में विलंब से क्रियान्वयन में इसके प्रभावी प्रयोग में बाधा आती है।

केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया में जोर दिया गया है कि समतुल्य वितरण विभिन्न आयामों पर आधारित है, पर विपक्षी राज्यों का दृष्टिकोण है कि ये व्याख्यायें सतही हैं। आलोचकों का कहना है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अक्षमता भेदभाव का प्रमाण है। विपक्ष शासित राज्यों ने विलंब के बारे में चिन्ता प्रकट की है जिससे योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं होता है। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन फंडों का प्रभावी प्रयोग हो तथा शिकायतों को संबोधित करने के लिए क्रियान्वयन पर गहरी नजर रखी जाए। राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप, राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि केन्द्रीय

एजेंडिया राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना लगाती हैं जिनसे भेदभाव की भावना और मजबूत होती है। भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का आरोप है कि केन्द्रीय संसाधनों के प्रबंधन से सरकार इन जटिल राजनीतिक गतिशीलताओं का प्रबंधन आसानी से कर सकती है। भेदभाव के आरोपों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार को अनेक रणनीतियों का पयोग करना चाहिए जिनमें पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। उसे फंड आबंटन तथा खर्च की विस्तृत रिपोर्ट जारी करना चाहिए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा असमान वितरण को शिकायतें दूर हो सकें।

समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है। इसके साथ ही वैश्विक साझेदारी, रक्षा, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि भारत विश्व मंच पर प्रमुख पक्ष के रूप में उभरना चाहता है। बजट का प्रमुख ध्यान समावेशी विकास पर है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। ढांचगत सुधार पर काफी आबंटन किया गया है जिसमें सड़कें, रेलवे और डिजिटल ढांचे शामिल हैं। बजट न केवल रोजगार सृजन का वादा करता है, बल्कि दीर्घकालीन आर्थिक मजबूती के लिए जमीनी आधार भी तैयार करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा व हरित तकनीक पर जोर इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जो इसे टिकाऊ विकास की वैश्विक प्रवृत्तियों से जोड़ता है। लेकिन स्वास्थ्यरक्षा और शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर समुचित आबंटन खासकर कोविड-19 वैश्विक महामारी से सीखे सबकों के बाद जरूरी था। इसके साथ ही शिक्षा व खासकर डिजिटल व व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देना जरूरी है। इससे युवा पीढ़ी ऐसे कौशल से लैस होगी जो उसे भविष्य में रोजगार बाजार के लिए तैयार करेगी। मानव पूंजी के विकास पर जोर देना दीर्घकालीन टिकाऊ विकास के लिए बहुत जरूरी है। वित्तीय समावेशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उसकी

सहायता करने की वास्तविक सफलता महिला फोल्ड वर्कर्स द्वारा दिखाई गई प्रतिक्रिया और करुणा के कारण है। एक साल की परियोजना के अंत में परियोजना के निष्कर्ष बताते हैं कि महिला फोल्ड जागरूकता और स्क्रीनिंग में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुई। एक मानवीय स्पर्श कैसे एक मानवीय स्पर्श सभी अंतर ला सकता है, यह ताहिरा के मामले में देखा गया। शांति ने ताहिरा को उसके चुनौतीपूर्ण उपचार के दौरान सिर्फ काउंसलिंग के जरिए ही नहीं, बल्कि एक एनजीओ के साथ अपने संपर्कों के जरिए हर महीने भोजन राशन की खुराक देकर भी मदद की। इसके अलावा, उन्होंने उसे एनटीईपी की अक्षय पोषण योजना से भी जोड़ा, जो टीबी पीड़ितों को भोजन खरीदने के लिए हर महीने 500 रुपये देने की सरकारी योजना है। टीबी से ठीक हो चुकी महिलाओं को एक्टिविस्ट और फोल्ड वर्कर्स के तौर पर तैनात करने से उन लोगों तक पहुंचने में भी मदद मिली है जो टीबी से पीड़ित हैं। वे जानती हैं कि टीबी के साथ जीने का क्या मतलब है और उन्हें किस तरह के सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने के उनके दृढ़ संकल्प ने शुद्धात्मी पहचान और उपचार को बढ़ावा दिया है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि सबसे ज्यादा जोखिम में वे लोग हैं जो खराब हवादार और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में रहते हैं, कुपोषण और बीमारियों से पीड़ित हैं और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी सीमित पहुंच है। प्रोजेक्ट लीड ने दिखाया है कि महिला फोल्ड ऑफिसर अपनी समझ और संवेदनशीलता को वजह से कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को टीबी की जांच और उपचार के लिए राजी करने में ज्यादा सफल होती हैं। टीबी शोधकर्ता डॉ. अनुराग भार्गव, डॉ. मधुकर पई और डॉ. माधवी भार्गव ने दोहराया कि टीबी एक इलाज योग्य संक्रामक रोग है जो असमानताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन असमानताओं को पाटने के लिए अधिक साझेदारी में निवेश करना और भी जरूरी है।

# निरंतरता व सहानुभूति से टीबी का उपचार

तपेदिक एक उपचार योग्य संक्रामक रोग है जो असमानताओं से जुड़ा है, इसलिए इन असमानताओं को सहानुभूति के साथ संबोधित करने वाली साझेदारियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।



स्वामि मजुमदार (लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं)

एक साल पहले 20 वर्षीय ताहिरा को यकीन हो गया था कि वह मरने वाली है। बुखार जो ठीक नहीं हो रहा था, लगातार खांसी, भूख न लगना और अत्यधिक कमजोरी ने उसे महीनों तक विस्तर पर रहने पर मजबूर कर दिया था। उसका पति, जो एक रिक्शा चालक है, के पास न तो साधन थे और न ही उसे डॉक्टर के पास ले जाने का समय। जब उसका भाई कोलकाता में उससे मिलने आया और उसकी गिरती सेहत को देखा, तभी उसने मानले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वह ताहिरा को अपने साथ दिल्ली के सीमानुपुरी में उसके मायके ले आया। यह फैसला उसकी जान बचाने के लिए था। लगभग इसी समय, एक गैर-लाभकारी

संस्था, ह्यूमैना पीपल ट पीपल इंडिया, अपने प्रोजेक्ट लीड (लीवरेजिंग एजुके टिंग, एडवोके टिंग टू डिस्परटी टीबी ट्रांसमिशन) के एक हिस्से के रूप में तपेदिक (टीबी) पर जानकारी और मार्गदर्शन दे रही थी। सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते हुए, लीड ने चार शहरों, दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और हैदराबाद में निम्न-श्रेणी की शहरी झुग्गियों में रहने वाले अक्सर उपेक्षित और उपेक्षित हाशिए के समुदायों, बेघर और प्रवासी आबादी पर ध्यान के द्रित किया। दृढ़ता का फल मिलाजब लीड फोल्ड ऑफिसर शांति ने ताहिरा से मुलाकात की, तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि क्या करना है। सबसे पहले, उसे छाती का एक्स-रे कराने के लिए ले जाया गया। जब ताहिरा में टीबी होने की संभावना दिखाई दी, तो थूक की माइक्रोस्कोपी की गई, जिसमें टीबी की पुष्टि हुई। एक बार जब यह स्पष्ट हो गया, तो कार्टिज-आधारित न्यूक्लियिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट के माध्यम से डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित आणविक परीक्षण और सरकारी जीटीबी

अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध कराए गए लाइन प्रोब परख के माध्यम से दवा संवेदनशीलता परीक्षण के माध्यम से निदान की पुष्टि की गई। दवा संवेदनशीलता परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि टीबी बैक्टीरिया (बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस), जो किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, जिनसे उनका इलाज किया जाता है। शांति को एहसास हुआ कि बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से नी-अक्षय, सरकार की एनटीईपी रियल-टाइम रोगी प्रबंधन वेब प्रणाली पर अपना पंजीकरण सक्षम किया, ताकि उसका कार्ड बनाया जा सके और उसका इलाज उसी दिन शुरू हो सके। एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में, शांति जानती थी कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और उपचार का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, अगले छह महीनों के लिए, शांति ताहिरा की छाया बन गई। उसने सतर्क नजर रखी और ताहिरा को दवा के नियम से चिपके रहने या चूकने से बचाने के लिए 40 बार लगातार उसका इलाज

किया। उसकी दृढ़ता का फल तब मिला जब कुछ महीने पहले ताहिरा का परीक्षण नकारात्मक आया और अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। टेकनो सीएटीटीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए जल्दी पता लगाना और इलाज करना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब वह बीमारी तब फैलती है जब बीमारी वाले व्यक्ति हवा में बैक्टीरिया छोड़ते हैं, ज्यादातर खांसने से। यहाँ पर तकनीक एक भूमिका निभा सकती है। कफ ऑप्ट टीबी (केट) एक अर्धनव अनुप्रयोग है जो वाधवानी एआई द्वारा विकसित फुफुसुसीय टीबी की संभावना का आकलन करने के लिए एआई-संचालित खांसी-ध्वनि-आधारित स्क्रीनिंग टूल है, जिसके परिणामस्वरूप 10.8 प्रतिशत संभावित दर और 15.6 प्रतिशत की सकारात्मकता उपज हुई। केट का उपयोग करने के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक स्पर्शानुख मामलों का पता लगाना था, जो अत्यथा छूट जाते। जबकि प्रौद्योगिकी एक सक्षम उपकरण रही है, 600,000 से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टीबी (पीडब्ल्यूटीबी) से पीड़ित 3,182 लोगों की पहचान करने और दिखें में

उम्र में से 98वें को उपचार के अनुपालन में सहायता करने की वास्तविक सफलता महिला फोल्ड वर्कर्स द्वारा दिखाई गई प्रतिक्रिया और करुणा के कारण है। एक साल की परियोजना के अंत में परियोजना के निष्कर्ष बताते हैं कि महिला फोल्ड जागरूकता और स्क्रीनिंग में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुई। एक मानवीय स्पर्श कैसे एक मानवीय स्पर्श सभी अंतर ला सकता है, यह ताहिरा के मामले में देखा गया। शांति ने ताहिरा को उसके चुनौतीपूर्ण उपचार के दौरान सिर्फ काउंसलिंग के जरिए ही नहीं, बल्कि एक एनजीओ के साथ अपने संपर्कों के जरिए हर महीने भोजन राशन की खुराक देकर भी मदद की। इसके अलावा, उन्होंने उसे एनटीईपी की अक्षय पोषण योजना से भी जोड़ा, जो टीबी पीड़ितों को भोजन खरीदने के लिए हर महीने 500 रुपये देने की सरकारी योजना है। टीबी से ठीक हो चुकी महिलाओं को एक्टिविस्ट और फोल्ड वर्कर्स के तौर पर तैनात करने से उन लोगों तक पहुंचने में भी मदद मिली है जो टीबी से पीड़ित हैं। वे जानती हैं कि टीबी के साथ जीने का क्या मतलब है और उन्हें किस तरह के सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने के उनके दृढ़ संकल्प ने शुद्धात्मी पहचान और उपचार को बढ़ावा दिया है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि सबसे ज्यादा जोखिम में वे लोग हैं जो खराब हवादार और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में रहते हैं, कुपोषण और बीमारियों से पीड़ित हैं और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी सीमित पहुंच है। प्रोजेक्ट लीड ने दिखाया है कि महिला फोल्ड ऑफिसर अपनी समझ और संवेदनशीलता को वजह से कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को टीबी की जांच और उपचार के लिए राजी करने में ज्यादा सफल होती हैं। टीबी शोधकर्ता डॉ. अनुराग भार्गव, डॉ. मधुकर पई और डॉ. माधवी भार्गव ने दोहराया कि टीबी एक इलाज योग्य संक्रामक रोग है जो असमानताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन असमानताओं को पाटने के लिए अधिक साझेदारी में निवेश करना और भी जरूरी है।

## आप की बात

**मनु की दुहरी सफलता**  
पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 12 साल बाद निशानेबाजी स्पर्धा में दो पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और हम भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। खेलों में मनु भाकर की सफलता ने सिद्ध किया है कि बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं हैं। उन्होंने अपने हौसलों से हर मुश्किल काम को आसान किया है और हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। ओलंपिक में एक बार फिर मनु ने हमें गर्व करने का अवसर प्रदान किया है। ओलंपिक के 124 सालों के सफर में भारत ने अब तक 35 पदक ही हासिल किए हैं और इनमें मात्र 10 स्वर्ण पदक हैं। 10

**मीडिया की जिम्मेदारी**  
दिल्ली से छपने वाले अखबारों में शायद ही ऐसा कोई दिन हो कि किसी कोचिंग संस्थान का पूरे पेज का विज्ञापन न छपा हो। विडंबना है कि जैसे ही ये कोचिंग संस्थान विज्ञापनदाता हो जाते हैं, मीडिया का ध्यान इस बात से हट जाता है कि इनके भीतर कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। शायद फल मिलाजब लीड फोल्ड ऑफिसर शांति ने ताहिरा से मुलाकात की, तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि क्या करना है। सबसे पहले, उसे छाती का एक्स-रे कराने के लिए ले जाया गया। जब ताहिरा में टीबी होने की संभावना दिखाई दी, तो थूक की माइक्रोस्कोपी की गई, जिसमें टीबी की पुष्टि हुई। एक बार जब यह स्पष्ट हो गया, तो कार्टिज-आधारित न्यूक्लियिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट के माध्यम से डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित आणविक परीक्षण और सरकारी जीटीबी

**ट्रेन दुर्घटना**  
हावड़ा से मुंबई जा रही मेल एक्सप्रेस झारखण्ड में चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 20 बोगियां बेपत्ती हो गईं जिससे 2 यात्रियों की मृत्यु हुई और अनेक घायल भी हो गए। हालांकि, रेलवे ने मृतक आश्रितों, गंभीर घायलों और मामूली घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक के बाद एक दुखद रेल दुर्घटनायें कहीं कहीं गंभीर लापरवाही दर्शाती हैं। यह जांच का विषय है कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। लेकिन इनसे रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। हालांकि रेलवे वर्तमान समय में

**कर्नाटक का निर्णय**  
भारतीय न्याय संहिता-बीएनएस की धारा 281 के तहत वाहनों की गति 120 किलोमीटर से अधिक होने पर खतरनाक ड्राइविंग मानी जाती है। इसीलिए कर्नाटक राज्य सरकार ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ़्तार से गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ एक अगस्त से एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उचित और स्वागत योग्य है। यह निर्णय इसलिए भी उचित है क्योंकि इससे अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है और दुर्घटना का अंदेश हमेशा बना रहता है। आजकल

# हमारी सरकार ने खोले आठ लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते: योगी

● वर्तमान सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत राज्यांश को बढ़ाकर किया 14 प्रतिशत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधान परिषद् में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को लेकर वक्तव्य दिया। एनपीएस पर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के बाद राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाता खोलने का कार्य किया गया।

उन्होंने कहा कि 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई तब प्रदेश में मुलाहम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा सरकार थी। वहीं 2007 से 2012 तक बसपा और फिर 2012 से 2017 तक सपा सत्ता में थी, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी कर्मचारी के पेंशन खाते नहीं खोले गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018 में जब

न्यू पेंशन स्कीम पर सीएम योगी ने विधानपरिषद में सपा-बसपा को लताड़ा, कहा, 2005 से 2017 तक नहीं खोले गए पेंशन खाते



ये बात हमारे सज्जन में आई, तब हमने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। इसमें संबंधित विशेषज्ञों को भी रखा गया। कर्मचारी संगठनों से भी चर्चा की गई। ये लगभग आठ लाख कर्मचारियों से संबंधित मुद्दा था। तब ये बात सामने आई थी कि कर्मचारी

की लास्ट पेमेंट जो ड्रॉ होगी उसका 50 प्रतिशत देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेर थोड़ा और बढ़ाए। आंकलन में पता लगा कि अगर सरकार और कर्मचारी समय से पैसा जमा करें और कर्मचारी किसी स्कीम से अपना पैसा जोड़ता है तो रिटायरमेंट के बाद करीब 60

प्रतिशत तक पैसा पेंशन के रूप में उसे प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हमने पेंशन स्कीम में सरकार के शेर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया है। हमने सभी कर्मचारियों के अकाउंट खोले, 2005 से 2017 तक का पैसा जो कर्मचारियों के खाते में नहीं गया था, क्योंकि खाता ही नहीं था, उस पैसे को भी खोलने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के वक्त जिन कर्मचारियों को नियुक्ति अंतिम चरण में थी, ऐसे 70 हजार लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा, इनमें एक बड़ी संख्या शिक्षकों की है। सीएम योगी ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को प्राइवेट बैंकों में जमा करने की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और इसमें कार्रवाई भी की गई है, साथ ही धनराशि को वापस लाने का कार्य किया गया है। सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी

लाल बिहारी यादव को उच्च सदन में नेता विरोधी दल बनाने पर दी बधाई

इससे पहले मुख्यमंत्री ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनाने पर बधाई दी और चुटकी लेते हुए कहा कि आशा करता हूँ कि आप हमेशा नेता विरोधी दल बने रहें। उन्होंने कहा कि ये उच्च सदन है, यहां आने वाले माननीय सदस्यगण सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ स्थानीय निकाय, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कुछ स्नातक मतदाताओं व माननीय राज्यपाल जी के मनोनयन से यहां आते हैं। सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पीठ से जो भी आवश्यक दिशा-निर्देश मिलते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है।

सरकारी स्कीम का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जुड़े।

माजपा नेताओं को राहुल गांधी से आजादी की लड़ाई का हिसाब पूछना चाहिए: अजय राय

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा नेताओं को राहुल गांधी से आजादी की लड़ाई का हिसाब पूछना चाहिए। 1947 तक जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी वह चांद पर कैसे पहुंच गया और मंगल पर जा रहा है, पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया 5 सैन्य ताकतों में से एक बन गया इन सब का हिसाब पूछना चाहिए। साथ ही साथ खुद भी बताना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस और भाजपा के आकाओं ने देश के साथ गद्दारी क्यों की और पिछले 10 साल से देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने आजादी के लिए सिर्फ जेल नहीं काटी बल्कि देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान निखार कर दी और शहीद हो गए। संघ और भाजपा के लोगों को राहुल गांधी के परिवार के बहते हुए रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब भी मांगना चाहिए और खुन की जाति भी पूछनी चाहिए। राय ने कहा कि ऐसा लगता है आरएसएस और भाजपा में घटिया से घटिया बोलने तथा कीचड़ में नहाने की होड़ लगी है, यह शर्मनाक है। देश और प्रदेश की सत्ता में बैठे भाजपा के लोग अपनी मर्यादा खो रहे हैं जो देश की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।

कांग्रेसियों ने अनुराग ठाकुर का फूका पुतला

लखनऊ। भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए कथित अमर्यादित बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में कांग्रेसजनों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर ठाकुर का पुतला फूका गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण के दौरान जननायक, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछने सम्बन्धी अमर्यादित बयान पर कांग्रेसजनों में भारी आक्रोश है। राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाया जा रही है उससे देश का जनमानस कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहा है जिसका उदाहरण देश में कुछ दिनों पूर्व हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राहुल गांधी की द्वारा जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाने जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है, और अनुराग ठाकुर का यह बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। पर अब देश की जनता भाजपा की जनविरोधी नीतियों को भलि भांति पूर्वक समझ चुकी है और आने वाले समय में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में कांग्रेसजनों ने आज जिला/शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष देव प्रकाश त्रिपाठी, अमित श्रीवास्तव त्यागी एवं डॉ. शहजाद आलम के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर भाजपा के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर पुतला का नारा लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया तथा पूर्व मंत्री का पुतला फूका। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसजनों को बलपूर्वक रोका गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा पुलिस प्रशासन के लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई।

## यूपी में अपराधियों को पुलिस का तनिक भय नहीं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाख दावे करें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है परन्तु हकीकत में तो यही लगता है कि अपराधियों को पुलिस का तनिक भी भय नहीं रह गया है। रोज ही दबंगों द्वारा भूमि पर कब्जे, अपहरण, लूट और महिला अपराध के मामलों सुर्खियां बटोरते हैं। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था कैसे सुधर सकती है जब स्वयं सत्ता से जुड़े लोग ही संरक्षण का लाभ उठाकर मनमानी करने पर उतारू हो रहे हैं।

अखिलेश जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कयार गांव में होसला बुलंद बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तीन महीने पहले उसका पिता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजधानी लखनऊ में दोस्तों ने अपने दोस्त की निर्ममता से हत्या कर दी।



नवाबगंज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप किया गया। बाद में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यों तो छिन्ती और लूट की घटनाएं तो आए दिन की बातें हैं। व्यापारियों के साथ लूट की तमाम घटनाएं हुई हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब राजधानी में ही किसी न किसी महिला की चैन या पर्स नहीं लूटा जाता हो। आज कल तो साइबर क्रॉस भी बहुत बढ़ गया है। टगी की घटनाएं कम नहीं हो रही है। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज में खेत से घर आ रही युवती से रेप का प्रयास किया गया। उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई। हरदोई के सांडी क्षेत्र में गोबर खलने घर से निकली किशोरी की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्यारो ने उसकी आंख भी फोड़ दी। लखनऊ में घर में काम करवाने के बहाने से बुलाकर 12 साल की बालिका से दुष्कर्म किया गया। कारखाने में महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। अखिलेश ने कहा कि कबरेली के

## अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए पुलिस अफसरों को डीजीपी ने दी विदाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए पुलिस अफसरों को डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस मुख्यालय में समारोह आयोजित कर विदाई दी। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, रूचिता चौधरी पुलिस अधीक्षक महिला एवं सुरक्षा संगठन व अष्टभुजा प्रसाद सिंह पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज को डीजीपी ने मोमेंटो भेंट किया। सेवाकाल के दौरान गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने उनके एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। सुनील कुमार गुप्ता वर्ष 1993 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। वर्ष 2009 में पुलिस उपमहानिरीक्षक और 2013 में पुलिस



महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए। वर्ष 2018 में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस महानिदेशक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद, पुलिस महानिदेशक उग्र के जनरल स्टॉफ ऑफिसर एवं अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार के पदों पर नियुक्त रहे। वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय के पद पर नियुक्त थे। रूचिता चौधरी वर्ष 1994 में प्रान्तीय पुलिस सेवा में चयनित हुईं। वर्ष 2006 में अपर पुलिस अधीक्षक

के पद पर प्रोन्नत हुईं। वर्ष 2021 में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा का कैडर हासिल हुआ। वर्तमान में वह पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (1090), लखनऊ के पद पर नियुक्त थीं। अष्टभुजा प्रसाद सिंह वर्ष 1999 में प्रान्तीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। वर्ष 2013 में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए। वर्ष 2019 में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा का कैडर हासिल हुआ। वर्तमान में वह पुलिस अधीक्षक, रेलवे प्रयागराज के पद पर न्युक्त थे।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक जोएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

## एससीआर व नजूल संपत्ति विधेयक विधानसभा में पारित

● नजूल संपत्ति विधेयक के तहत नजूल भूमि को संरक्षित कर इसका सार्वजनिक उपयोग करेगी सरकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक के साथ ही उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति, 2024 विधेयक भी पारित हो गया। इन दोनों विधेयकों को योगी सरकार ने अस्थादेश लाने के बाद निर्धारित समयसीमा के अंदर विधानसभा में प्रस्तुत किया और इस पर सदन की मुहर लावा दी। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक के तहत एससीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रोजन का गठन किया जाएगा। विधेयक के पारित होने के बाद लखनऊ और उसके पड़ोसी जिलों ज्जाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, और बाराबंकी को मिलकर एससीआर का गठन किया जाएगा, जिससे इन जिलों का उचित, व्यवस्थित और

लखनऊ, ज्जाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, और बाराबंकी के लोगों को एनसीआर की तर्ज पर मिलेगी सुविधाएं

त्वरित विकास हो सकेगा। वहीं नजूल संपत्ति विधेयक 2024 के तहत सरकार ने नजूल भूमि को संरक्षित करते हुए इन भूमियों को निजी व्यक्तियों/संस्थाओं के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में घोषित करने के बजाय इसका उपयोग केवल सार्वजनिक उपयोगिता के लिए किए जाने का निश्चय किया है। दोनों ही विधेयकों को विधानसभा में पारित हो गए एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। विधेयक पारित होने के बाद विधायित्व को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन विधेयक-2024 के माध्यम से राज्य सरकार का उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके गठन के लिए राज्य सरकार पर किसी प्रकार का व्यय भार प्रस्तावित नहीं है। इसके तहत सभी 6 जिलों के 27 हजार 860 वर्ग मीटर

परिया को समेटकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। इससे इन सभी जिलों में तेज विकास किया जा सकेगा और यहां रहने वाले लोगों को एनसीआर की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की सकेगी। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय एवं विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास और गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी परिियोजनाओं, जन्मुविधाओं का समूचे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकास होगा। योजना गत क्षेत्रीय विकास से आवासन, अवसंरचना, यातायात, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी। वहीं, उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति विधेयक, 2024 के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश

में स्थित नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में प्रतिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्यवाही या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन, निरस्त हो जाएंगे और अस्वीकृत समझे जाएंगे। यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है, तो ऐसे जमा किए जाने की तारीख से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मॉर्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लॉडिंग रेट (एससीएलआर) की ब्याज दर पर कैलकुलेट करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, के पट्टों को सरकार या तो ऐसे शर्तों पर जैसा सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है जारी रख सकती है या ऐसे पट्टों का निर्धारण कर सकती है।

## नेता सदन ने दी है सुरक्षा की गारंटी: सुरेश खन्ना

● परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर सपा सदस्य आए वेल में

● नजूल सम्पत्ति विधेयक-2024 प्रस्तुत होने पर विपक्ष बिफरा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सदस्य विजमा यादव अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर वेल में पहुंच गयीं। उनके बाद समाजवादी पार्टी के बाकी सदस्य भी वेल में पहुंच गए। सपा सदस्य विजमा यादव का कहना था कि उनके पति हत्यारोपी की सजा माफ किए जाने के साथ ही उनकी सुरक्षा में भी कटौती की गयी है जिससे उन्हें और परिवार को जान का खतरा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने हत्यारोपी की सजा माफ किए जाने पर सवाल उठाया। इस पर

विधानसभा

कवररिया की सजा माफ कर उसे रिहा किए जाने से उनकी और परिवार की सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना था कि इस बात कल ही सदन में नेता सदन और मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार सदस्य विजमा यादव और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेती है। उनकी मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर जो भी आवश्यक होगा किया जायेगा। सपा सदस्य का कहना था कि उनके पति के हत्यारोपी की सजा माफ किए जाने के साथ ही उनकी सुरक्षा में भी कटौती की गयी है जिससे उन्हें और परिवार को जान का खतरा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने हत्यारोपी की सजा माफ किए जाने पर सवाल उठाया। इस पर

शिवपाल ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के मध्य बैठक कराने का उदाया मुद्दा

सपा के वरिष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सिंह ने जिलों में सलाहकार समितियों के गठन न होने और उनकी बैठकें न होने का मामला उठाया। सपा के शिवपाल यादव ने भी जिलों में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की बैठक न बुलाए जाने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सरकार जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराए। जबवा संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हर जिलें में जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराए जाने के आज ही निर्देश निर्गत करायेंगे।

उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि जिला सलाहकार समितियों का गठन सुनिश्चित कराने के संबंध में मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि जिलों में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें करें और उनके फोन भी रिसीव करें। पूर्व

में भी मुख्य सचिव की ओर से इस आशय के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। नियम 301 के तहत कांग्रेस की सदस्य आराधना मिश्रा मोना ने सदन के सदस्यों का वार्षिक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने का मामला उठाया। इस पर विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सरकार जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराए। जबवा संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हर जिलें में जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराए जाने के आज ही निर्देश निर्गत करायेंगे।

समस्याओं को लेकर सपा के कई सदस्यों ने सवाल किए जिस पर गन्ना विकास मंत्री चैधरी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार सत्तारूढ होने के बाद गन्ना किसानों का भुगतान शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जा रहा है। सपा के सदस्य समरपाल सिंह का आरोप था कि सरकार गन्ना किसानों को तीन का भुगतान नहीं किया गया है। एक अनुपूरक के जवाब में कहा कि केन्द्र के शुगर एक्ट में परिवर्तन करने का राज्य सरकार कोई अधिकार नहीं है। आज ही सदन में दिवंगत पूर्व लोकसभाध्यक्ष मनोहर जोशी तथा प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डा अजीज कुरैशी सहित पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान, डा अच्युतानंद तिवारी, शफीकुर रहमान वर्क, राम छबीला, मुखार अंसारी, छोटे लाल यादव, विनय शाक्य, बाबूलाल कुशवाहा सहित अन्य सदस्यों के निधन पर शोक जताया गया।

## नजूल संपत्ति विधेयक जनविरोधी: आराधना मिश्रा

● कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने कहा, इस कानून के बहाने भाजपा सरकार कर रही गरीबों का आशियाना छीनने की साजिश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता में आराधना मिश्रा 'मोना' ने जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाए। नियम प्रमुख रूप से नजूल संपत्ति प्रबंधन विधेयक 2024 में जनहित में संशोधन करने और घरेलू कूड़ा निस्तारण में सुधार का मुद्दा उठाया और इसे धरातल पर लागू करने की बात कही।

मोना ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में लाए गए नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को जनविरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जनता के लिए जनदेश की संख्या का तानाशाही दुरुपयोग बताया है। मोना ने कहा की सरकार इस कानून में संशोधन करें यह कानून गरीबों के घरों को उजाड़ने का कानून है, और जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बनाये आशियाने को उजाड़ने वाला है, प्रदेश के लाखों लोगों को बेघर करने वाला है, इस



कानून का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग होगा। मोना ने कहा कि सरकार ने कानून में यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि नजूल की भूमि पर सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल बने हैं तो उसके लिए इस कानून से छूट दी जायेगी और गरीब आदमी के घर को इस कानून से उजाड़ दिया जायेगा यह भेदभाव कैसे, संविधान समान अधिकार कानून के समान रूप से लागू करने की बात करता है, जिन लोगों ने अपने नजूल जमीन को फ्री होल्ड कर लिया है, या जो लोग पैसा जमा कर चुके और अभी फ्री होल्ड नहीं हो पाया उनके लिए जनदेश की संख्या का तानाशाही दुरुपयोग बताया है। मोना ने कहा की सरकार इस कानून में संशोधन करें यह कानून गरीबों के घरों को उजाड़ने का कानून है, और जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बनाये आशियाने को उजाड़ने वाला है, प्रदेश के लाखों लोगों को बेघर करने वाला है, इस

मोना ने जनहित से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे घरेलू कूड़ा निस्तारण में अभावस्था और भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही लापरवाही के मुद्दे को उठाया और भाजपा सरकार की नाकामी से पर्यावरण के नुकसान की बात कही। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण आज के समय का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सरकार द्वारा निस्तारण संबंधी संयंत्र की बातें हवा लापरवाही से प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार की तरफ से कूड़ा निस्तारण में बातें तो हो रही हैं, कूड़ा संयंत्रों की संख्या गिनाई जा रही लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम पदार्थ हैं जिनके रिसावकल में लापरवाही हो रही है। आराधना मिश्रा मोना ने कहा की प्रदेश की सरकार को लापरवाही से सैकड़ों लोग बीमार हो रहे हैं, सरकार इस पर सिर्फ बातें न करे इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

## ईओडब्लू ने वित्तीय निगम के पूर्व सहायक प्रबंधक को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया

● लाखों रुपए गबन के मुकदमे में थी तलाश, डेस कार्नेर नोटिस भी हुआ था जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लाखों रुपए गबन करने वाली फर्म के साथ आपराधिक साजिश में शामिल रहने के आरोपी अनिल कुमार खन्ना, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक, (टैक्निकल) उअ वित्तीय निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा को स्वीटजरलैंड से लौटते ही ईओडब्लू ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। खन्ना के खिलाफ ईओडब्लू ने रेंड कानर्न नोटिस भी जारी करवा रखा था। दुर्गा वायर एण्ड फिलामेन्ट प्रा.लि., ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के प्रमोटर्स द्वारा पूर्व नियोजित



आपराधिक षडयन्त्र कर उअ वित्तीय निगम, क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा से 37,05,000 रुपए शॉर्ट टर्म लोन लेने तथा उक्त फर्म के प्रोराइटर पंकज खन्ना तथा उअ वित्तीय निगम के तत्कालीन सहायक प्रबन्धक अनिल कुमार खन्ना के साथ दुरभित्ति कर गबन किए जाने के सम्बन्ध में थाना सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी विवेचना उअ शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2000 को ईओडब्लू को हस्तान्तरित की गई। उक्त अभियोग से सम्बन्धित आरोपी वांछित अभियुक्त अनिल कुमार खन्ना निवासी एम-21, साकेत मन्दिर मार्ग, दिल्ली की गिरफ्तारी के लिए

21.6.2017 को उसके विरुद्ध रेंड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। 29.7.2024 को अभियुक्त अनिल कुमार खन्ना उपरोक्त को इन्ट्रा गांधी ईरेंडरनशल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर ज्यूरिक (स्विटजरलैण्ड) से भारत आने पर रोका गया। उक्त एयरपोर्ट के अधिकारियों से उक्त आशय की सूचना प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम से पुलिस अधीक्षक, ईओडब्लू मेट्र सेक्टर द्वारा अभियोग की विवेचक नोतू राणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर 29.7.2024 को ही अभियुक्त अनिल कुमार खन्ना का न्यायालय से 14 दिवस रिमाण्ड स्वीकृत करते हुए उसे न्यायिक अभिक्षा में लिला कारागार गौतमबुद्धनगर भेज दिया गया।

# जिलाधिकारी-एसपी ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण

**लखीमपुर खीरी।** कारागार प्रशासन द्वारा बन्दिनों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर कारागार की साफसफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल व एसपी गणेश प्रसाद साहा ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की।

डीएम,एसपी ने बंदी ग्रह में जाकर बंदियों का हालचाल जाना एवं खाने,पीने के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही जेल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न बैरिकों में जाकर बंदियों से मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कारागार में साफसफाई व्यवस्था मिलने पर संतोष व्यक्त किया। निर्देश दिए कि इसी प्रकार प्रतिदिन जेल में साफसफाई बनाए रखी जाए।

डीएम,एसपी ने सभी बैरिकों व



बंदियों का गहन निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान बैरिकों में किसी प्रकार की आपत्तजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। जेल अधीक्षक की ओर से बताया गया कि नियमित रूप से उनके व जेल स्टाफ की ओर से जेल की चेकिंग की जाती है। डीएम,एसपी ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि नियमित रूप से कारागार का निरीक्षण

करते रहें। संवेदनशील बंदियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। समय,समय पर कारागार में निरूद्ध बंदियों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी देते रहें। कारागार अधीक्षक पीडी सलोनियाए जेलर हरिवंश कुमार पांडेय, डिप्टी जेलर धीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर, भोजराज सिंह, चिकित्सक डॉ शिवपूजन मौजूद रहे।

## डीएम ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय का किया निरीक्षण, सफ सफाई के लिए निर्देश

**कानपुर देहात।** जिलाधिकारी आलोक सिंह के द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय अंतर्गत विभिन्न पटलों से संबंधित कार्यों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने कार्यालय में साफ सफाई व्यवस्थाए पत्रावलियों के रख,रखाव दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पटलों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया की शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार सभी कार्य समय अंतर्गत पूर्ण किए जाएं। उन्होंने परियोजना निदेशक को पुरानी निष्प्रयोग वस्तुओं की नोलामी करने हेतु निर्देशित किया। इस मौके पर परियोजना निदेशक वीरेंद्र कुमार व कार्यालय संबंधित स्टाफआदि उपस्थित रहे।

## जनपद के दिव्यांग छात्र-छात्राएं निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति हेतु करें आनलाइन आवेदन

**कानपुर देहात।** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयए भारत सरकारए नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति संचालित है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े दिव्यांग छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण है। उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के माध्यम से दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना प्री.मैट्रिक छात्रवृत्तिए आरंभ करने की तिथि 30.06.2024 अंतिम तिथि 31.08.2024 है, इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति व उच्च श्रेणी शिक्षा 30.06.2024 से 31.10.2024 है। जनपद के दिव्यांग छात्र-छात्राएं निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

# सीडीओ के अध्यक्षता में हुई जनपदीय खरीफ गोष्ठी, किसानों को दी लाभकारी जानकारी

## ● वैज्ञानिकों को सुझाए बेहतर खेती के गुर, साझा की जानकारी



**लखीमपुर खीरी।** बुधवार को कलेक्ट्रेट में सीडीओ अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खरीफ गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को लाभकारी खेती करने के लिए उपयोगी जानकारी दी। गोष्ठी में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख बेहजम/नकहा/मोहम्मदी तथा जिला पंचायत सदस्य ने प्रतिभाष किया।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शासन, प्रशासन करते संकल्पित होकर काम कर रहा। इसके लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानपरक योजनाओं के

अपनाएंगे व आसपास के अपने जानने वाले किसानों तक भी तकनीक को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उपस्थित किसानों को अन्न जैसे सवाएँ कोदो तथा रागी के मिनी किट भी वितरित किये गये। खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का संचालन डीडी कृषि ने किया। कृषि वैज्ञानिक डॉ पीके बिसेन ने खरीफ की फसलों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। किसानों को फसल बीमाए प्राकृतिक खेती तथा आईपीएम/समन्वित नाशी जीव प्रबन्धनइ विधि से कीड़े, बीमारियों की रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

# चरित्र के शक में पति ने अपनी पत्नी का सिर काटकर पैदल थाने पहुंचा

**बांदा।** बांदा में सन 2000 में चरित्र के शक में पति ने अपनी पत्नी का सिर काटकर अपने हाथ में लेकर दिनदहाड़े बीच बाजार से पैदल चलते हुए ठाणे पहुंचा था इस पर पूरा बरेबर तहसील के लोग विचलित हो गए थे उसे आज बांदा सत्र न्यायालय के जिला जज ने फंसी की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार उर्फ मुन्नू परिहार व एडीजीसी उमाशंकर पाल ने बताया कि 9 अक्टूबर 2020 को बरेबर थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार कस्बे के नेता नगर निवासी किन्नर यादव पुत्र दयाराम ने अपनी पत्नी विमला की परसे से वार करते न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि उसकी कटी हुई गर्दन को हाथ में लेकर पैदल ही थाने पहुंच गया था।

मृतका के पिता रामशरण यादव निवासी अमलोहरा बिसंडा की तहरीर के आधार पर दामाद उसकी पुत्री पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता

था और इसी वजह से उसने दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। बताया है कि हत्यारीपी किन्नर ने पड़ोसी युवक रविकांत शर्मा को भी खुरपे से वार करके घायल कर दिया था।

तत्कालीन थानाध्यक्ष जयश्याम शुक्ला ने मृतका के पिता की तहरीर पर धारा 302 व 324 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले को गहन विवेचना की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय बहादुर सिंह परिहार और अपर शासकीय अधिवक्ता अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी किन्नर यादव को दोषी करार दिया और मृत्युदंड की सजा सुनाई।

# भारी पुलिस बल के बीच जेसीबी द्वारा तोड़ा गया अतिक्रमण, हुई कहासुनी

संवाददाता। बिंदकी (फतेहपुर)

**भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा अतिक्रमण को तोड़ा गया अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कई बार कहा-सुनी भी हुई।** इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी तथा राजस्व विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बुधवार को नगर के ललौली रोड मोहल्ला स्थित मैनी कुआं के समीप भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा अतिक्रमण को तोड़ा गया। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कर्मचारी राजस्व टीम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कई बार कहा सुनी और नोक झोंक हुई। बताया चलें कि एक सप्ताह पहले इसी स्थान पर अतिक्रमण को दलीलें सुनने के बाद आरोपी किन्नर यादव को दोषी करार दिया और मृत्युदंड की सजा सुनाई।



एक बार फिर अतिक्रमण को तोड़ने का काम किया गया। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता अरुण कुंभार सक्सेना, सहायक अभियंता संतोष कुमार कर्नाजिया, अवध अभियंता अजीत सिंह, नायब तहसीलदार

अरविंद कुमार, राजस्व निरीक्षक रघुराज सिंह, लेखपाल भान सिंह, लेखपाल अजीत उमराव, लेखपाल वीरेंद्र श्रीवास्तव तथा पुलिस बल के साथ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे, कस्बा इंचार्ज नीरज कुशवाहा मौजूद रहे।

## कार्यवाही: डीएम ने तीन भण्डारणकताओं पर ठेका 34 लाख का जुर्माना

**लखीमपुर खीरी।** जनपद खीरी में अवैध खनन, परिवहन पर अंकुश लगाने प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के मार्गदर्शन में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने तीन भण्डारणकताओं पर 34 लाख का जुर्माना लगाया और कूटचित्त मउ311 मामले में पट्टाधारक पर एफआईआर के निर्देश दिए। माह जुलाई 2024 में तहसील धौरहा के शारदाधर और तहसील पलिया के भण्डारणकताओं द्वारा स्वीकृत मानक के सामूहिक अधिक मात्रा में साधारण बालू का भण्डारण पाया गया तथा सेन्टाट रोड पर स्थित एक अवैध डम्प सागबालू का पाया गया। उक्त तीनों भण्डारणकताओं से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर लगभग 34900 लाख रूपये का अर्थदंड आरोपित किया गया और कूटचित्त मउ311 जारी किये जाने के सम्बन्ध में डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए एक पट्टा धारक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए।

## विक न्यूज़

### डंपरो को आमने सामने भिंडत से चालक की मृत्यु दो जख्मी

**मौदहा (हमीरपुर)।** बीती रात छिरका गांव के पास दो डंपरो में हुई आमनेसामने भिंडत में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वालनों का आवागमन टप ही गया। घटना की जानकारी लेते हुए मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दुर्घटनावास्त डंपरो को राजमार्ग से हटावा घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मंगलवार की दे रात रामनगर पुत्र गोपाल निवासी जहानाबाद जनपद फतेहपुर अपने खलासी साथी रामचंद्र के साथ डंपर में गिट्टी लाद हमीरपुर की ओर आ रहा था तभी बिपरीत दिशा से आ रहे दूसरे डंपर की भिंडत हो गयी इस डंपर का चालक नईम (26) पुत्र सलीम निवासी घाटमपुर बताया कजाता है। डंपरो के टकराने से उनका मलवा सड़क में फैल गया जिससे जान लगाने से मार्ग के दोनों ओर वालनों की लंबी कतार लगा गई। पुलिस ने मौके पर जाकर चालक रामचरण व रामचंद्र को निकाल लह लुखन खलत में सड़करी अस्पताल मौदहा में भर्ती कराया जबकि दूसरे डंपर के चालक नईम की मौके परही मौत हो गयी। इस राजमार्ग में ड्राइवइर न होने के चलते आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में लोग अकसय ही काल के गाल में समा रहे हैं। पुलिस ने शव को परीक्षण के लिये भेज दिया है।



### हत्या में वॉखित अभियुक्तगण गिरफ्तार

**कानपुर देहात।** अपराधियों व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के ऋण में दिनांक 2907072024 को वादी द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर गु030080 19202024 धारा 103,12661,226,228 भारतीय न्याय सिस्टम,बीपीएन0एचएड व धारा 3,2दए एससीधस्टटी एएट बनान 04 नएक नामजद अभियुक्तगण शिवम उर्फज्जाला सिंह पुत्र रामबहादुर पात निवासी गान गणेशपुर निवासी गान गणेशपुर निवासी गान गणेशपुर पुत्र सचो 200 थानू दवाल संखवार निवासी गान फरीदपुर निवासीगुलाब संखवार उर्फ अमरजोत पुत्र रामऔतार संखवार निवासी गान मंगलपुर थाना मंगलपुर पुत्रा देवी पत्नी गंगा गुरुचन्दन निवासी गान मंगलपुर थाना मंगलपुर पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 04 वॉखित अभियुक्तगण को गैरहे दर्शन झंडक डेह टाला थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारइतुअ अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### यमुना में डूबे युवक का मर्दधाम के पास शव बरामद

**फतेहपुर।** कानपुर नगर के थाना सगेती गांव बहरीली निवासी अपदेश सघान का पुत्र कपिल सघान अपने कुछ सहियों के साथ मंगलवार की दोपहर यमुना में नहाने गया था। तभी अचानक वह गहरे पानी में डूब गया। तब बहाव के कारण वह बहता हुआ निकल गया। वहीं साथ में आए देस्तो ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। जिस पर मौके पर पुलिस व गोताखोरो ने उसे ढूँढने का प्रयास किया। दो घंटे बाद पुत्रुए थाने के वरदई धाम के पास से गोताखोरो ने शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को रिक्केटन गृह भेज दिया। परिजनों ने कोहराना मय गया।

### ट्रक की चोटे में आकर बाइक सवार की मौत

**फतेहपुर।** सदर कोतवाली क्षेत्र के आधरपुर गांव निवासी कृषी का पुत्र सतेजन अपने साथी अंकुश पुत्र गंगाधर 18 वर्ष के साथ बाइक से आनी बहन के चरव गुलेर गांवा जा रहे थे। जैसे ही वे लोग शिवांव गांव के पास पहुंचे तभी आ रहे ट्रक की चोटे में आ गए जिससे सतेजन की घटनास्थल पर मौत हो गई वहीं अंकुश गंभीर रूप से घायल से गया। पुलिस ने घायल को तत्काल सड़करी एंबुलेंस से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा, जहां चिकित्सक ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए कानपुर के लिए पेश कर दिया। पुलिस ने शव को रिक्केटन गृह भेज दिया।

### काली नदी में कूदे अर्धेड का शव कुसुमखोर क्षेत्र में मिला

**गुरसहरखोर (कन्नौज)।** विगत दिन पूर्व किसी बात से आहत होकर अर्धेड ने रामाश्रम में स्थित काली नदी में कूद गया। नदी किनारे अर्धेड की साइकिल व कपड़े मिलने पर नदी में डूबने की आशंका से पुलिस की मौजूदगी में गानगी गोताखोरो ने खोजबीन शुरू कर दी थी। शुधवार की शाम 05 बजे अर्धेड का शव सदर थानाक्षेत्र की कुसुमखोर पुलिस चौकी क्षेत्र में मिला। जिससे परिजनों में कोहराना मय गया। ज्ञात से कि बीते सोमवार की शाम 06 बजे क्षेत्र के गाम संतुप स्थित रिस्टेदार की रह रहे 45 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र राधेपाल किसी बात से आहत होकर साइकिल पर सवार होकर रामाश्रम में स्थित काली नदी के किनारे साइकिल के कहियर पर घायल व कपड़े रखकर काली नदी में कूद गया था।

## बीआरसी पर एआरपी को महिला के भेष में आए हमलावर ने मारी गोली

**फर्रुखाबाद।** कमलगंज बीआरसी पर मौजूद आरपी के महिला के बेस में आए हमलावर ने पेट में गोली मार दी। जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई उन्हें शहर के एक निजी नर्सिंग होम में उपचार हेतु भर्ती किया गया। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम रूनी चुरसई निवासी विश्राम सिंह की कमलगंज क्षेत्र के नौगंवा में प्रधानाचार्य के पद पर तैनाती है। वह एआरपी के पर धी हैं। बुधवार को वह कमलगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र पर मौजूद थे, इस दौरान बताया जा रहा है कि महिला के वेश में कोई हमलावर बीआरसी कार्यालय पहुंचा और उसने देखकर विश्राम सिंह रामपूत के पेट में गोली मार दी इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए इस उधे नाला मस्करटा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया स मौके पर पुलिस में जाँच की। बीआरसी के सीसीटीवी खराब घटना के बाद मौके पर थाना पुलिस पहुंची, पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालने का प्रयास किया।

# 16 साल से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग में प्रवेश दिया तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

## ● आदेश नहीं माना तो एक लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी

**फतेहपुर।** कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में कोचिंग संचालकों पर एक लाख रुपये जुर्माना और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही होगी। डीआईओएस राकेश कुमार ने सभी कोचिंग संचालकों को सेवाएं नहीं ले सकेंगे, जो नैतिक कटाचार से जुड़े किसी भी अपराध के साक्ष्य दिखाने निर्देश जारी किए हैं। डीआईओएस ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों की आत्महत्या के बड़ते मामलों, आंग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण

पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद गाइड लाइन जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंका की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। अपराधिक व्यक्ति से नहीं ली जा सकती सेवाएं; कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति को सेवाएं नहीं ले सकते, जो नैतिक कटाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।

# माटीकला ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण हेतु करें आवेदन

**कानपुर देहात।** जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि प्ब090 माटीकला बोर्डर्प् के अन्तर्गत सूक्ष्मकत्री माटीकला ग्रामोद्योग रोजगारप् योजना संचालित की गयी है। जिसमें वर्ष.2024.25 के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कार्यक्षेत्र उद्यम की स्थापना ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अनुमन्य है। परियोजना का अधिकतम आकार.२00 10.00 लाख तक है। पात्र उद्यमी अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो एवं अभ्यर्थी उ090 का मूल निवासी हो आवेदक द्वारा माटीकला बोर्ड के पोर्टल पर आनलाईन आवेदन किया जायेगा। आपेक्षित दस्तावेज आवेदक का फोटोग्राफ शैक्षिक व तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण,पत्र आधार कार्ड, जाति प्रमाण,पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि है। शैक्षिक व तकनीकी योग्यता अभ्यर्थी का साक्षर अनिवार्य हैए २0. 5.00 लाख से अधिक

परियोजनाओं हेतु लाभार्थी को कम से कम 8 वर्षों कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा एवं अभ्यर्थी को ऋण लेने से पूर्व माटीकला का प्रशिक्षण प्राप्त/माटीकला की परम्परागत जानकारी हो।

परियोजना की मंजूरी तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार राष्ट्रीयकृत/ ग्रामीण बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी प्रदान की जायेगीए जो नियमानुसार 5 वर्ष के लिये होगी। वित्तीय स्रोत एवं सहायता प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा, जिसमें से पूंजीगत ऋण धनराशि पर 25 प्रतिशत मार्जिन मानी के रूप में शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन आनलाईन उपरान्त कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ( बैंक ऑफ इण्डिया के प्रथम तल पर ) चिटिकपुर चौराहा रनियां कानपुर देहात में 15.08.2024 तक जमा कर सकते हैं।

# कई गांवों में घुसा पानी चेतवनी बिंदु पर पहुंची गंगा

संवाददाता। फर्रुखाबाद

गंगा में एक बार फिर उमन मार दिया है। आज गंगा का जलस्तर चेतवनी बिंदु पर पहुंच गया। जिससे कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। अधिकारियों ने बाढ़ का जायजा लिया समत दिन से गंगा का जलस्तर 5 सेंमी बढ़ गया।

गंगा 136.60 मीटर यानी चेतवनी बिंदु पर आ गयी। गंगा में 99141 क्यूसेक पानी नदीरा बैराज से छोड़ा गया। राजेपुर गंगापर में गंगा का जल स्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चोटे में आ गये हैं। सैकड़ों बीघा मक्का, तीली की फसल नष्ट हो गयी। जिन गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है उन गांव की विवृत आपूर्ति बंद की गयी है।

थानाध्यक्ष रणविजय सिंह, एसडीओ सुरजित कुमार गुप्ता, अवर अभियंता विद्युत विभाग हरिओम कुमार ने क्षेत्र के गांव तीस राम की

## आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत

**फर्रुखाबाद।** कमलगंज थाना क्षेत्र में आज बुधवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक गृह स्वामिनी महिला की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीगौरामपुर निवासी वीरपाल की पत्नी गृहस्वामिनी फूलमती उम्र करीब 40 वर्ष आज बुधवार को अपने मकान की छत पर झोपड़ी में खाना बना रही थी कि दोपहर में बारिश के बीच तेज कड़क के साथ बिजली की गर्जना हुई और इसी दौरान अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झोपड़ी से बाहर निकली गृह स्वामिनी महिला की मौत हो गई। इस महिला को समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सरकारी चिकित्सक डा. विकास कुमार ने उसे अमृत घोषित कर दिया। महिला के चार पुत्र और एक पुत्री हैं। महिला के पति का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना मिलते ही फर्रुखाबाद सदर के तहसीलदार श्री कर्नौजिया तथा पुलिस स्टेशन में जाकर घटना के बारे में पुलिस समन बंद हो गया है गांव में आधा दर्जन लोग बुखार खुजली से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में नहीं पहुंची है।

## आठ परिषदीय विद्यालयों में केवल एक शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक चला रहे विद्यालय

### ● रिपोर्ट में एक विद्यालय को एक साल में कई शिक्षक रंगाई पुताई का कर रहे है दावा,टीवी के स्थान पर खाली डिब्बा मिला चार्ज में,दर्जी की दुकान नही मगर ड्रेस सिलवाने का किया गया दावा

संवाददाता। मौदहा (हमीरपुर)

**कस्बे** के आठ परिषदीय विद्यालयों में केवल एक शिक्षक नियुक्त है। जो सभी विद्यालयों का वित्तीय कार्य भी देख रहा है। सभी विद्यालय शिक्षा मित्र व अनुदेशक के भरोसे चल रहे हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र में दस बच्चों में दो अध्यापक व तीन शिक्षक नियुक्त है। इस स्थिति में जमकर वित्तीय घोटाले हो रहे हैं। सबसे ज्यादा घोटाला विद्यालयों की मंटीनेस में बताया जाता है जिसकी सुगबुगाहट होना शुरू हो गयी है।

जानकारी के मुताबिक शासन की तरफ से परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न मदों में लाखों रुपये की धनराशि आवंटित होती मगर इस धन का जमकर दुरुपयोग होती है

## आठ परिषदीय विद्यालयों में केवल एक शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक चला रहे विद्यालय

### ● रिपोर्ट में एक विद्यालय को एक साल में कई शिक्षक रंगाई पुताई का कर रहे है दावा,टीवी के स्थान पर खाली डिब्बा मिला चार्ज में,दर्जी की दुकान नही मगर ड्रेस सिलवाने का किया गया दावा

इधर कुछ अध्यापकों ने दूसरे स्कूलों में जाकर चार्ज लिया है तो वित्तीय घोटाले सामने आने शुरू हो गये हैं। मौदहा नगर क्षेत्र में इस दौरान आठ प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें मात्र एक शिक्षक की तैनाती है जो नगर क्षेत्र के शंकुल प्रभारी का काम भी देखते हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा के तैनाती है कि हर हाल में एक शिक्षक तो विद्यालय में नियुक्त होना चाहिये इधर ज्यादातर शिक्षक अपने मूल स्थान पर पहुंच गये जिससे स्थितिवा बेहद खराब हो गयी है। शिक्षक मूल स्थान पर तो पहुंच गये मगर अपना चार्ज नहीं छोड़ा है। ताकि उनके द्वारा कीगयी वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी उजागर न हो सके एक विद्यालय के अध्यापक द्वारा खरीदने के बाद खराब एलीडी टीवी छोड़ा गया था जो डब्बे के माडल और कम्पनी से मैच नहीं कर रही है इतना ही नहीं एक सरकारी विद्यालय के भवन को नगरपालिका और शिक्षा विभाग दोनों के द्वारा पुतवाने की बात सामने आ रही है जबकि चौधराना में एक ही कमरे में चल रहे टीवी स्कूलों को एक ही शैक्षिक सत्र में सभी के प्रधानाचार्य ने रंगवाने और पुतवाने का काम किया है इतना ही नहीं आरटीआई के तहत मांगे गए आय व्यय के बिल



मौदहा का बीआरसी विद्यालय

बाउचरों में बीआरसी द्वारा बांदा के जिस टेलर से कुछ साल पहले ड्रेस सिलवाने के बिल की फोटो कापी भेजी गई है वह टेलर एक दशक पहले अपनी दुकान बंद कर सूत की एक कम्पनी में रेंडीमेड कपड़ों की सिलाई कर रहा है इतना ही नहीं एक दशक पहले जो स्कूलों के खातों में पैसा पड़ा हुआ था उसे भी अध्यापकों ने निकाल कर ठिकाने लगा दिया है। जिसके चलते सम्पूर्ण चार्ज देने के बाद बड़े खुलासे का अनुमान है हालांकि विभाग इस मामले को बाहर आने देगा या कार्यवाही करेगा इस बात की उम्मीद कम है।इस सम्बंध में खण्ड शिक्षा अधिकारी रामगोपाल वर्मा ने बताया कि सभी अध्यापकों को दो दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है और शुक्रवार दो बजे सभी को



मौदहा का बीआरसी विद्यालय

बुलाया गया है उनके आने के बाद ही चार्ज नहीं देने की वजह साफहो सकेगी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

## बौएसए ने कहा समायोजन की कार्यवाही शुरु की जा रही

**हमीरपुर।** इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आलोक सिंह का कहना है कि शासन से समायोजन करने की कार्यवाही शुरुआत की जा रही है। आज इसी बात को लेकर बैठक हुई है। ट्रांसपर करना उनके अधिकार में नहीं है। शिक्षकों की वैसे ही कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय में कई ई शिक्षक है इस पर बीएसए का कहना है कि इसी मामले की समीक्षा की जा रही है। मगर फिर भी इस मामले में देखा जा रहा है।

### वया बोले सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला

**हमीरपुर।** इस मामले में सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला का कहना है कि इस मामले को वह गंभीरता से जांच करायेंगे,हालांकि ट्रांसपर पोस्टिंग अब सीधे शासन से होती है बीएसए के अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं रह गया है। फिर भी वह बीएसए से बात करके शिक्षकों की नियुक्ति करायी जायेगी शिक्षकों की वैसे भी बहुत कमी है।

# भाजपा विधायक ने गोवा में शराबबंदी की मांग की

**भाषा।** पणजी

**गोवा** विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक प्रेमन्द्र शेट ने तटीय राज्य में शराबबंदी की मांग की जिससे उनको ही पार्टी के कई सदस्य असहमत दिखे। सदन में मंगलवार को शेट ने कहा था, विकसित भारत और विकसित गोवा के लिए गोवा में शराब की खपत पर रोक लगाई जानी चाहिए। हम राज्य में शराब का उत्पादन कर सकते हैं और इसे दूसरे राज्यों को निर्यात कर सकते हैं, लेकिन गोवा में इसकी खपत पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उत्तरी गोवा के माापम विधानसभा क्षेत्र से पहली बार निर्वाचित भाजपा विधायक ने अपनी मांग के पक्ष में दलील दी कि राज्य में शराब की बढ़ती खपत के कारण सड़कों और औद्योगिक इकाइयों में

दुर्घटनाओं से लोगों की मौत होती है। हालाँकि, सदन में उनकी पार्टी के विधायक ही इस मांग से सहमत नजर नहीं आए।

भाजपा की महिला विधायक डेलिलाह लोबो ने बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में आश्चर्य जताया कि क्या शेट चाहते हैं कि लोग अपने रेस्तरां व्यवसाय बंद कर दें। लोबो अपने पति माइकल लोबो (कैलंगुट विधायक) के साथ उत्तरी गोवा के तटीय क्षेत्र में होटलों की एक श्रृंखला की मालिकन हैं। उन्होंने जिसके कारण, शराब यह कारण है जिसके कारण पर्यटक यहां आते हैं। हम क्या करें... क्या हमें रेस्तरां बंद कर देना चाहिए?

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक क्रूज सिल्वा ने कहा कि गोवा में शराब पर प्रतिबंध लगाना

संभव नहीं है। उन्होंने कहा, यहां सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन गोवा के लोग इसमें शामिल नहीं होते। यहां बहुत सारे रेस्तरां और अन्य व्यवसाय हैं जो शराब की बिक्री पर निर्भर हैं। शराब पर प्रतिबंध से रोजगार प्रभावित होगा। भाजपा विधायक संकल्प अमोनकर ने कहा कि वह शराब के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने राज्य में शराब के आदी लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में पहले भी विधानसभा में प्रश्न उठाया था, लेकिन वह शेट के विचारों से सहमत नहीं हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के एक अन्य विधायक केदार नाइक ने कहा कि गोवा एक पर्यटन राज्य है और शराब पर्यटन उद्योग का एक हिस्सा है। कई स्थानीय लोगों का व्यवसाय राज्य में शराब बेचने संबंधी उद्योग पर निर्भर है।

## लोगों को जबरन बेदखल करने और घरों के तोड़ने के मामले में आजम खान बरी

**रामपुर।** उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अदालत ने

यहां ड्रैगरपुर इलाके में लोगों को उनकी जमीन से जबस बेदखल करने और घरों को तोड़ने के पांच वर्ष पुराने मामले में सपा के नेता आजम खान को बुधवार को बरी कर दिया। राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद खान और पांच अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को उनके घरों से बेदखल किया और मकानों को ध्वस्त करने का काम किया। हालांकि अदालत से रहत मिलने के बावजूद खान सीतापुर जेल में ही रहेंगे। खान कई अन्य मुकदमों के सिलसिले में जेल में बंद हैं पीडित इदरसी नाम के व्यक्ति ने थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसपर सांसद-विधायक अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सधी आरोपियों को बरी कर दिया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान स्वास्थ्य खराब होने के कारण अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया, आजम खान और पांच अन्य को इस मामले में बरी कर दिया गया। खान के साथ-साथ ठेकेदार बरकत और चार अन्य को भी इस मामले में बरी किया गया है।

## दंगों के बाद मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने वाले समूह के खिलाफ प्राथमिकी आदेश

**पाटन ( गुजरात )।** गुजरात के पाटन जिले की एक अदालत ने पिछले साल जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक गांव में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किए जाने का कथित तौर पर आव्हान करने वाले लोगों के एक समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एच पी जोशी की अदालत ने हाल में एक आदेश में बलिसाना पुलिस थाने के उपनिरीक्षक को याचिकाकर्ता मकबूल हुसैन शोख की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने और समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि बलिसाना में कुछ लोगों ने 16 जुलाई, 2023 को सांप्रदायिक दंगे की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर स्थानीय लोगों को मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए उकसाया।

उन्होंने बलिष्कार में कहा, इस कदम से क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों के व्यवसाय और आजीविका प्रभावित हुई है और कुछ को तो यह स्थान छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। अदालत ने निर्देश दिया कि समूह पर विभिन्न समूहों के बीच दुरमनी को बढ़ावा देने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की

## भूखलन प्रभावित क्षेत्र में विषम परिस्थितियों के बावजूद बचावकर्मों डटे हैं अपने मिशन में

**वायनाड ( केरल )।** केरल के भूखलन प्रभावित वायनाड में उपन्नती नदियों पर अस्थाई पुल बनाने तथा मंलबों को हटाने में भारी मशीनों के लगे रहने के साथ ही बुधवार को बचाव अभियान जारी रहा। सैन्यकर्मियों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों, राज्य आपात सेवा के कर्मियों, स्थानीय लोगों समेत बचाव कार्य में शामिल सरकारी एवं गैर सरकारी लोग इलाके में वर्षा जारी रहने एवं अन्य विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने मिशन में लगे हुए हैं। बुरी तरह प्रभावित गाँवों में से एक, मुंडकई में, कटे हुए क्षेत्र से जुड़ने और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रक्सियों एवं सीढ़ियों की मदद से छोटे पुल बनाए गए।

उफनती नदियों के उम्र बने अस्थाई और संकरे पुलों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों समेत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा था तो कई बार तनावपूर्ण क्षण

सामने आए। कुछ स्थानों पर बचावकर्मियों ने लोगों को सुरक्षित निकाली सुनिश्चित करने के लिए रक्सियों का इस्तेमाल करते हुए मानव पुल बनाए। जोखिम भरे इलाकों में लोगों को लकड़ी के तख्त पर बिटा कर उफान पर आई नदी को पार कराया गया। चूँकि ज्यादातर मकान जर्माटोज होचुके हैं, ऐसे में बचावकर्मों छत तोड़कर रस्सी के सहारे घर में घुसे ताकि वह पता किया जा सके कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, लगातार उफनती नदी बचाव मिशन जमीन, उपन्नती नदी बचाव मिशन की राह में चुनौतियां पेश कर रही हैं। कई बचाव एजेंसियों ने लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के मद्देनजर सुबह ही बचाव अभियान शुरू कर दिया। मंगलवार की सुबह मूसलाधार बारिश के कारण हुए बड़े पैमाने पर भूखलन ने मुंदकई, चूलमाला, अट्टामाला और न्लपुसा बस्तियों को प्रभावित किया।

### नाइसाफ़ी के बावजूद हम राजग केसाथ बने रहे : पारस

**पटना।** पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (राजोपा) के साथ नाइसाफ़ी हुई लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ बने रहने का फैसला किया। बिहार में राजग के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पारस ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। पारस, पार्टी की एक बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन के बाद बेलीजाप आर्िस्त्व में आई थी। पारस ने कहा हालांकि लोकसभा चुनाव में हमें बुरा लगा लेकिन हमने अपनी वफादारी नहीं बदली। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे समझेंगे और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमें उचित प्रतिनिधत्व देंगे।

## भारत में पशुओं के लिए चारे की कमी : राजीव रंजन सिंह

**नई दिल्ली।** मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत में पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति का संकट है। सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया देश में चारे की कमी है। आईसीएआर-भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई) झांसी ने अनुमान लगाया है कि देश में हरे और सूखे चारे की क्रमशः 11.24–32 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की कमी है। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार पशु चारे की कमी से अवगत है? सिंह ने बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग 2014–15 से चारा और चारा विकास पर एक उप मिशन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लागू करके राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को मदद दे रहा है। भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई झांसी–

आईसीएआर) ने 25 ग्रामों के लिए चारा संसाधन विकास योजना तैयार की है, ताकि राज्यों में उनके फसल पद्धति और पशुधन प्रजातियों के आधार पर चारे की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। एक अलग प्रश्न के उत्तर में, सिंह ने कहा कि देश में दूध का उत्पादन 2018–19 में 18.77 करोड़ टन से बढ़कर 2022–23 में 23.06 करोड़ टन हो गया है। देश में सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उप्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। राज्य मिलकर देश के कुल दूध उत्पादन में 53.08 फीसदी का योगदान करते हैं। सिंह ने कहा कि भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत का योगदान देता है। मंत्री ने कहा, पिछले 9 वर्षों में दूध उत्पादन लगभग 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रति दिन है। हम फेरलू मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर हैं।

## कांग्रेस की बंगाल इकाई में आसन्न बदलाव पर माकपा एवं तृणमूल की करीबी नजर

**भाषा।** कोलकाता

**कांग्रेस** की पश्चिम बंगाल इकाई में आसन्न नेतृत्व परिवर्तन पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी करीब से नजर रख रही हैं, क्योंकि इससे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तीनों दल विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं लेकिन कांग्रेस-वाम गठबंधन पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एवं मुख्य विपक्षी भाजपा दोनों का विरोध करता है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में पश्चिम बंगाल के प्रभारी एवं पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुयब रहें अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के

प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में राज्य इकाई के नए प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इस साल 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस-वाम गठबंधन और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें तृणमूल ने एक ही कुल 42 सीट में से 29 पर, भाजपा ने 12 और कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की।

मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर से पांच बार के सांसद रहे चौधरी तृणमूल उम्मीदवार एवं क्रिकेटर यूसुफ पटन से हार गए थे। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पहचान गुप्त रखते हुए पीटीआई-भाषा को बताया, हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तृणमूल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन राज्य में अधीर रंजन चौधरी के विरोध के कारण गठबंधन नहीं हो सका। उन्होंने हम पर नियमित रूप से

हमला करके राज्य में भाजपा के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की।

तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भी इसी तरह की भावना प्रकट की। चौधरी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर माकपा ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने पीटीआई-भाषा से कहा, अगला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, यह उनका आंतरिक मामला है। अधीर चौधरी ने वामदलों के साथ मिलकर बंगाल में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह राज्य में तृणमूल एवं भाजपा दोनों का विरोध करने वालों में प्रमुख थे। हालांकि, वाम मोर्चा के एक अन्य नेता ने चिंता व्यक्त की कि यदि कांग्रेस बंगाल में तृणमूल के करीब जाती है, तो मौजूदा वाम-कांग्रेस गठबंधन खतरे में पड़ सकता है।

### पूजा...

सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें सीएसई–2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। सीएसई–2022 के लिए उसकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उसे भविष्य की सभी परीक्षाओं/यूपीएससी के चयन से स्थायी रूप से वॉचत कर दिया गया है। पैनल ने कहा है कि पूजा खेडकर प्रकरण के मद्देनजर, उसने 2009 और 2023 के बीच आईएसएस स्कीनिंग प्रक्रिया को मंजूरी देने वाले 15,000 से अधिक उम्मीदवारों के डेटा की जांच की थी। इस विस्तृत अभ्यास के बाद, सुश्री पूजा मनोहरा दिलीप खेडकर के मामले को छोड़कर, किसी अन्य उम्मीदवार को सीएसई नियमों के तहत अनुमति से अधिक संख्या में प्रयासों का लाभ उठाते हुए नहीं पाया गया है। सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के अकेले मामले में, यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मूल्यांकन से इस तथ्य के कारण उनसे प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगा सकी क्योंकि उन्होंने न केवल अपना नाम बर्लिक अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था। बयान में कहा गया है कि यूपीएससी यह सुनिश्चित करने के लिए एसओपी को और मजबूत करने की प्रक्रिया में है कि भविष्य में ऐसा मामला दोबारा न हो। यूपीएससी ने स्पष्ट किया कि वह उम्मीदवारों के केवल प्रमाणपत्रों की प्रारंभिक जांच करता है। आम तौर पर, प्रमाणपत्र को असली माना जाता है, अगर वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

### भाजपा मे शामिल हो सकती हैं राज्यसभा से इस्तीफा देने

**वाली बीजद नेता ममता मोहंता नई दिल्ली।** राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाली बीजू जनता दल (बीजद) की नेता ममता मोहंता के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन को कार्यवाही के दौरान बताया कि ममता ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ममता मोहंता अप्रैल 2020 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थीं और वह महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य थीं। ममता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति की भी सदस्य थीं। ओडिशा विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत है और उनके इस्तीफे के बाद होने वाले उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का निर्वाचित होना लगभग तय है।

## सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी करार देने के लिए साझा मंशा होना पर्याप्त है: उच्च न्यायालय

**मुंबई।** बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा है कि सामूहिक बलात्कार के मामले में अगर किसी एक आरोपी ने यौन कृत्य किया और बाकियों का ऐसा करने का इरादा था तो यह उन्हें सबूत में शामिल मानने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इस बारे में पर्याप्त सबूत होने चाहिए। उच्च न्यायालय ने पूर्वी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर में 2015 में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने और उसके पुरुष मित्र पर हमला करने को लेकर चार लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी। दो दोषियों ने अपनी अपील में दावा किया कि उन्हें सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे महिला के यौन उत्पीड़न में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपराध से पहले उनकी ऐसा करने की कोई मंशा भी नहीं थी।

न्यायमूर्ति जी. ए. सनप की एकल पीठ ने मंगलवार को उपलब्ध हुए चार जुलाई के आदेश में दोनों दोषियों को दल दलीलों को टुकार दिया और कहा कि उन्होंने उस समय पीड़िता के मित्र को पकड़ रखा था। पीठ ने कहा कि अगर दोनों ने पुरुष मित्र को पकड़ कर न रखा होता तो वह शीर मचाकर दो अन्य व्यक्ति्यों को पीड़िता के साथ धिनीनी हरकत करने से रोक सकता था। अदालत ने कहा, सामूहिक बलात्कार के मामले में अगर किसी एक आरोपी ने यौन कृत्य किया और बाकी आरोपी उसमें किसी तरह से शामिल थे तो यह उन्हें अपराध में शामिल मानने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके पर्याप्त सबूत होने चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, मुझे लगता है कि दो दोषियों की हरकत ने बलात्कार के कृत्य में दो अन्य दोषियों की मदद की।

अदालत ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी करार देने और 20 साल जेल की सजा सुनाने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली चारों दोषियों की अपील खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जून 2015 में पीड़िता और उसका पुरुष मित्र एक मंदिर गए थे और बाद में एक वन क्षेत्र में बैठे थे, तभी चार आरोपियों ने खुद को वन रक्षक बताते हुए उनसे पैसे मांगे। जब पीड़िता शौच के लिए गई तब दो आरोपियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया, जबकि बाकी दो ने उसके पुरुष मित्र को पकड़ रखा था। इलाके से गुजर रहे वन रक्षक ने महिला को चीख सुनी और मौके पर पहुंचे, तब चारों आरोपी फरार हो गए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने चारों दोषियों के खिलाफ मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। पीठ ने कहा कि पीड़िता के साक्ष्य, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य चारों आरोपियों के अपराध को साबित करते हैं।

### उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओडिशा के बंदरगाह पर चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया

**पारादीप ( ओडिशा )।** ओडिशा में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों ने एक चीनी मालवाहक जहाज को कब्जे में लिया है। उच्च न्यायालय ने मौद्रिक विवाद पर जहाज को कब्जे में लेने के आदेश दिया था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। नौबंद कर्मी कानून के तहत, किसी भी जहाज के स्वामित्व, निर्माण, प्रबंधन, संचालन या व्यापार से उत्पन्न होने वाले समुद्री दावों के क्रियान्वयन के लिए जहाज को कब्जे में लिया जा सकता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का यह आदेश जहाज के मालिक और माल भेजने वाली कंपनी के बीच मौद्रिक विवाद के बाद आया है। माल भेजने वाली कंपनी ने कम सल्फर वाले समुद्री गैस तेल की खेप भेजी थी। जहाज अगले आदेश तक बंदरगाह पर ही रुका रहेगा। माल भेजने वाली कंपनी ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि जहाज के मालिक ने उसे 99.81 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। पेश किए गए दस्तावेज और दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने सोमवार को जहाज को कब्जे में लेने का आदेश दिया ।

## पेज 1 का शेष

### शाह का ...

के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। विजयन ने कहा, यह आरोप-प्रचारों का समय नहीं है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 91 लोगों का इलाज चल रहा है जबकि 240 लोग लापता हैं। मेरी सरकार ने जिले के 82 राहत शिविरों में 8107 लोगों को रखा है। मौसम विभाग ने बारिश या भूखलन को लेकर कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया था। मुंडकई में भूखलन के कुछ घंटों बाद मंगलवार सुबह 6 बजे जीएसआर ड्राइ रेट अलर्ट जारी किया गया। भूखलन मंगलवार सुबह 2 बजे और 4.30 बजे हुआ। केंद्रीय जल आयोग, जो बाढ़ की चेतावनी जारी करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, ने ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की।

### कोचिंग सेंटरों...

मकान मालिकों द्वारा अत्यधिक किराये, आग की मंजूरी, नालों से गाद निकालने और छात्रों की अन्य तत्काल जरूरतों से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करेगा। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा, समिति कोचिंग संस्थानों को विभिन्न स्थानों से धीरे-धीरे एक सुनियोजित क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना तैयार करेगी। मुख्य सचिव छात्रों के व्यापक हित में,

शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप, कोचिंग संस्थानों/ट्यूशन कक्षाओं के लिए दिशानिर्देश/नियामक ढांचा तैयार करने का मामला उठाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीवीए) एक शिक्षा केंद्र की स्थापना के लिए पहले कदम के रूप में, जो सभी कोचिंग संस्थानों को समायोजित करेगा, नरेला और रोहिणी में चिन्हित स्थानों पर कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए साइट विजिट की सुविधा प्रदान करेगा। बेसमेंट में लाइब्रेरी या शिक्षण सुविधा चलाने वाले किसी भी कोचिंग संस्थान को तुरंत सील कर दिया जाएगा। इस बात पर सहमति हुई कि एक अल्पकालिक उपाय के रूप में, संस्थान, विशेष रूप से बड़े संस्थान छात्रों को अपने भवनों की अन्य मंजिलों पर पढ़ने के कामरे के रूप में स्थान प्रदान करके सहायता करेंगे। राज निवास के अनुसार, कोचिंग संस्थानों का महासंघ तीन मूत छात्रों के शोक संतप्त परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सहमत हुआ। उन्होंने उन नामांकित छात्रों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शुल्क में छूट देने की भी पेशकश की, जिन्हें

मानसिक पीड़ा और पढ़ाई में व्यवधान का सामना करना पड़ा है। राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि पैनल विनियमन, अत्यधिक किराये, आग की मंजूरी, नालों से गाद निकालने और छात्रों की अन्य तत्काल जरूरतों से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करेगा। आयुक्त एमसीडी अनि मंजूरी और भवन उपनियमों के नियामक ढांचे को स्पष्ट करने के लिए अनिश्चान विभाग की एक बैठक बुला सकते हैं। पुलिस आयुक्त सभी बीट

कांस्टेबलों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम भी सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को सहायभूतिपूर्ण और सक्रिय सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने संपत्ति दलालों की पकड़ से उत्पन्न अपनी दुर्दशा को साझा किया, जो किराया अधिक वसूलते थे। उन्होंने किराये और अन्य भुगतानों के निपटारे में उनकी अर्थव्यवस्था की व्यापकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जो संस्थाएं नैतिकता को एक विषय के रूप में पढ़ती हैं, वे स्वयं अनैतिक प्रथाओं के दोषी हैं। यहां तक कि मकान मालिकों द्वारा लिया जाने वाला बिजली शुल्क 24 रुपये प्रति यूनिट तक था, जो आवासीय शुल्क से काफी अधिक था। अत्यधिक शुल्क वसूलने के बावजूद भी तंग आवास और शिक्षण सुविधाएं प्रदान की गईं। उन्होंने छात्रों के लिए किसी भी शिकायत निवारण तंत्र को गैर-मौजूदगी और कोचिंग संस्थानों के भीतर बुनियादी सुविधाओं की कमी और रिफंड हॉसिल करने में कठिनाई का मुद्दा भी उठाया। अधिकारियों के अनुसार खुले आदान-प्रदान के दौरान, विभिन्न हितधारकों ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए लघु और दीर्घावधि में अपने-अपने दृष्टिकोण और सुझाव सामने रखे।

### ईरान...

के लिए तेहरान में था। उसने बताया कि हिनएह तेहरान में अपने आवास पर यहूदी हवाई हमले में मार गया।

<sup>[1]</sup> मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा है कि सामूहिक

# आर्थिक वृद्धि, रोजगार के बीच संतुलन साधता है बजट, सभी वर्गों का ध्यान

भाषा | नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि बजट में आर्थिक वृद्धि, रोजगार, पूंजी निवेश और राजकोषीय मजबूती के बीच बेहतर संतुलन स्थापित के साथ सहयोगपूर्ण संघर्ष को बढ़ावा दिया गया है। सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। विश्व संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर वास्तव में दुष्प्रचार करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, 'बजट में आर्थिक वृद्धि, रोजगार, पूंजी निवेश और राजकोषीय मजबूती के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया गया है। यह आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ रोजगार बढ़ाने वाला है। सीतारमण ने कहा, बजट में सहकारी संघर्ष को बढ़ावा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों को 22.91 लाख करोड़ रुपए दिए गए जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.49 लाख करोड़ रुपए अधिक हैं। बजट में केवल दो राज्यों का नाम होने और अन्य की अनदेखी करने को लेकर अलोचना पर वित्त मंत्री ने कहा, अगर बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके लिए बजट में कोई आवंटन नहीं है। उन्होंने कहा, अगर पीछे के बजट को देखा जाए तो संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने भी अपने कई बजट भाषण में सभी राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया था।



सीतारमण ने कहा, 2004-05 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया। वहीं 2009-10 के पूर्ण बजट में 28 राज्यों का नाम नहीं था। अन्य बजट भाषण में भी कई राज्यों का उल्लेख नहीं था। क्या उन राज्यों को पैसा नहीं मिला? केंद्रीय करों में कम हिस्सेदारी के विपक्ष में आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाती है और केंद्र सरकार उसका पूरी तरह से पालन कर रही है। उन्होंने कहा, यह साफ होना चाहिए कि राज्यों को राशि शुद्ध कर राजस्व के आधार पर दी जाती है न कि सकल कर राजस्व के आधार पर। उपकर, सब्सिडी और कर संग्रह लागत

घटाकर शुद्ध कर राजस्व का निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) करता है। सीतारमण ने कहा, इसके उलट राजग सरकार ने राज्यों का जो भी बकाया है, उसका भुगतान समय पर किया है। उन्होंने कहा कि वित्त 10 साल में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को पूंजीगत व्यय 43.82 लाख करोड़ रुपए रहा जो एक दशक पहले संप्रग शासन के दौरान 2004-05 से 2013-14 के बीच 13.19 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने कहा, चालू वित्त वर्ष में 11.11 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का निर्धारण किया गया है। यह पूंजीगत व्यय मद में अबतक का सर्वाधिक आवंटन है। यह वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 17

प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट का मकसद भारत को विनिर्माण कंपनियों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना भी है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष में इसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 तक हम इसे 4.5 प्रतिशत से नीचे लाएंगे। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि इसके उलट इन सभी क्षेत्रों के लिए आवंटन पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। सीतारमण ने कहा कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 8,000 करोड़ रुपए अधिक है। इसी तरह शिक्षा पर आवंटन बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए किया गया है। सीतारमण ने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा, यह सबको पता है कि तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की गलत नीतियों से मुद्रास्फीति 22 महीनों तक दहाई अंक के करीब चली गई थी और यह वैश्विक औसत से अधिक रही थी। लेकिन आज यह काफी हद तक नियंत्रण में है। यह राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार की बेहतर नीतियों का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हुई है।

दैनिक नकदी प्रबंधन के लिए जे एंड के बैंक से हंडी और ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था का पुराना चलन अब समाप्त हो गया है। पिछले चार साल के दौरान, जे एंड के बैंक में उल्लेखनीय बदलाव आया है। बैंक को 2019-20 में 1,139 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन 2023-24 में उसे 1,700 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। वित्त मंत्री ने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार और युवा बनाए रखने में मदद करेगी और इसपर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। बजट चर्चा के दौरान चिदंबरम ने अग्निवीर योजना की आलोचना की और सरकार से इसे वापस लेने को कहा था। सीतारमण ने कहा कि यह योजना हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं और युद्ध की तैयारी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुधारत्मक कदम है। उन्होंने राज्यों में पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के संबंध में ध्रामक बयान देने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आड़े हाथ लिया। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष की आलोचना पर सीतारमण ने कहा, इससे परिवारों के लिए कम लागत में चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित हुई है। विशिष्ट रूप से इससे कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को नुकसान पहुंचा है। खासकर मेडिकल शिक्षा क्षेत्र के लोगों को क्योंकि अब मेडिकल सीटें बेचना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, यही कारण है कि एनईईटी लीक मामले सामने आने से पहले भी विशेष लांबी एनईईटी के खिलाफ सक्रिय थी।

## राज्यसभा में उठी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाए जाने की मांग

नई दिल्ली | (भाषा) राज्यसभा में बुधवार को संस्कृत की उपेक्षा पर चिंता प्रकट करते हुए इस प्राचीन भाषा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अनिवार्य विषय बनाने और विश्वविद्यालयों में इसके पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा शोध के लिए विशेष अनुदान देने की मांग उठी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य दिनेश शर्मा ने (भाजपा) में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से संस्कृत साहित्य के डिजिटल स्वरूप का प्रचार-प्रसार करने, संस्कृत ग्रंथों के ऑनलाइन कोर्स आरंभ करने और इस भाषा में नाटकों, गीत और संगीत कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ावा देने की भी गुंजारिश की। संस्कृत भाषा को देश की सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय स्रोत करार देते हुए शर्मा ने कहा कि इसका साहित्य अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है और यहां तक कि वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे अनेक ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इनका

अध्ययन आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यह सभी ग्रंथ पुरातन ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं तथा इसमें निहित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। शर्मा ने कहा कि भारतवर्ष में आदिकाल से ही संस्कृत बोलचाल की भाषा रही है और तमाम भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत को अन्य सभी भाषाओं की जननी करार देते हुए भाजपा सदस्य ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ प्रदेशों में इसकी उपेक्षा बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी प्रभाव के कारण संस्कृत भाषा का अध्ययन दिन प्रतिदिन प्रचलन से दूर होता जा रहा है। विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रति रूचि घटती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी युवा पीढ़ी अपने प्राचीन ज्ञान से वंचित हो रही है। शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के उन्नयन का उल्लेख प्रसन्नता का विषय है लेकिन वह इसकी उपेक्षा की स्थिति को

सुधारने के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में संस्कृत के पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए और इस भाषा में शोध के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने देश में ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की मांग की जहां संस्कृत के साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई हो। शर्मा ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रूचि बढ़ेगी और उन्हें इसका व्यापक ज्ञान मिलेगा। उन्होंने कहा, संस्कृत साहित्य का डिजिटल रूप में अनुवाद और प्रसार किया जाए ताकि यह आसानी से उपलब्ध हो सके। संस्कृत ग्रंथों के ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार भी आयोजित किए जाने चाहिए। संस्कृत में नाटकों, कविताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि लोगों में संस्कृत के प्रति सम्मान बढ़ सके।

## भारत स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन विकसित करने पर काम कर रहा है

नई दिल्ली | (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारत स्वदेशी तकनीक से देश में बुलेट ट्रेन विकसित करने पर काम कर रहा है। वैष्णव ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना तकनीकी रूप से बहुत जटिल है और इसे जापान की मदद से क्रियान्वित किया जा रहा है। पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद और मुंबई के बीच निर्माणाधीन है। वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन दो पश्चिमी शहरों के बीच कुल 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें से 320 किलोमीटर हिस्से पर काम ज़ोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वाले हिस्से में काम धीमा हो गया था, लेकिन 2022 में भाजपा-शिवसेना-राकांपा की महायुक्ति सरकार के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई और राज्य सरकार से सभी प्रासंगिक अनुमतियां मिल गई हैं। उन्होंने कहा, अब काम बहुत तेजी से चल रहा है। मंत्री ने कहा कि समुद्र के नीचे भारत की पहली रेल सुरंग का निर्माण चल रहा है, जो 21 किलोमीटर लंबी होगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में भारत को बुलेट ट्रेन की तकनीक विदेशों से मिली थी, लेकिन अब देश में भी कई तकनीकें विकसित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने पर काम कर रहे हैं।

## नीट व्यवस्था कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी : सीतारमण

नई दिल्ली | (भाषा) मेडिकल पोटेंट्रिकमी से संबंधित राष्ट्रीय पाठ्य व प्रवेश परीक्षा (नीट) व्यवस्था की विपक्ष द्वारा तीखी आलोचना के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि यह प्रणाली कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। सीतारमण ने उच्च सदन में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि नीट को सबसे पहले 2010 में अधिभूषित किया गया था और तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं द्रमुक नेता जी सेल्वन के नेतृत्व में इसका कार्यान्वयन किया गया था। उन्होंने कहा कि 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में ही पहली नीट परीक्षा हुई थी। सीतारमण ने कहा कि 2011 में जब तमिलनाडु में द्रमुक का शासन समाप्त हुआ, उस समय राज्य में केवल 1,945 मेडिकल सीटें थीं जो अब बढ़कर 10,425 हो गई हैं और इस प्रकार पिछले 11 वर्षों में 8,480 सीटों की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नीट किसी के भी खिलाफ नहीं है लेकिन इससे कुछ निहित स्वार्थी को नुकसान हुआ है, खासकर मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि अब रैक बेचना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि एक विशेष लांबी नीट लीक मुद्दे के सामने आने से पहले ही इसके खिलाफ थी। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की नीति युवाओं को अधिक सक्षम बनाना है। चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कुछ सवाल उठाए थे। वित्त मंत्री सीतारमण ने उन सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि नीट को 2006 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया कि डीजीपी का चयन राज्य सरकार की ओर से विभाग के सबसे वरिष्ठ तीन सदस्यों में से से किया जाएगा जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की भी भूमिका होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के संबंध में भी उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है।

## प्रधानमंत्री से मिले शिवकुमार, कर्नाटक के लिए और अधिक धन की मांग रखी

बेंगलूर। कर्नाटक के उप- मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात की और राज्य में सिंचाई परियोजनाओं एवं बेंगलूरु के विकास के लिए अधिक धनराशि दिए जाने की मांग रखी। शिवकुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलूरु का गिफ्ट सिटी की तर्ज पर विकास किए जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के उस अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार नहीं किया गया था। हालांकि हमने सुरंग परियोजना, सिमल-मुक्त गलियारे, बेंगलूरु में मुख्य सड़कों और वर्षा-जल निकासी नालियों के विकास के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए और अधिक धन की मांग की है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलूरु राष्ट्रीय खजाने में दूसरा सबसे अधिक कर देने वाला शहर है लेकिन हाल के केंद्रीय बजट में इसे कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कर्नाटक को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, हेबबल और नेलमंगला में फ्लाईओवर के लिए धन मिला था। उन्होंने इस मुलाकात पर कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में केवल एक गिफ्ट सिटी (गुजरात) ही स्थापित की जा सकती है। इसलिए, हमने बेंगलूरु में शुरू की जाने वाली कई बड़ी परियोजनाओं में केंद्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। हमने बेंगलूरु को बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर जोर दिया है क्योंकि लाखों लोग बाहर से आ रहे हैं, जिससे बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ रहा है। शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने उमरी भद्रा परियोजना के लिए पिछले बजट में 5,300 करोड़ रुपए देने के बावजूद केंद्र द्वारा कोई धन जारी नहीं करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस मुद्दे को उठाने का वादा किया है।

## भारत, वियतनाम मक्त व्यापार समझौते की संभावना तलाशें: वियतनामी प्रधानमंत्री

नई दिल्ली | वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने के लिए बुधवार को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की संभावनाएं तलाशने का अनुरोध किया। चिन्ह इस समय एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में कई मंत्री, उप मंत्री और व्यापार जगत के दिग्गज शामिल हैं। उन्होंने वियतनाम-भारत व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों को अपना द्विपक्षीय व्यापार 20 अब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने उद्योग मंडल फिक्की की तरफ से आयोजित बिजनेस फोरम में कहा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम वियतनाम और भारत के बीच एक उपयुक्त एफटीए के माध्यम से एक-दूसरे के उत्पादों तक अपनी बाजार पहुंच बढ़ाएं।

## कोचिंग सेंटरों से विद्यार्थियों को बाहर लाना ही होगा

नई दिल्ली | (भाषा) स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि कोचिंग सेंटरों से विद्यार्थियों को बाहर लाना ही होगा और सबके सहयोग से इसके लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान प्रधान ने कहा कि विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कोचिंग संस्थानों की मदद लेते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान न हों और इसके लिए जरूरी है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो। सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इसकी मिसाल हैं। पूरक प्रश्नों के जवाब में प्रधान ने कहा कोचिंग सेंटर न हों, इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। अनेक राज्यों में पढ़ाई को लेकर बेहतर स्थान हैं। राजस्थान में सीकर ने बहुत ही बढ़िया काम अध्ययन में किया है। इसी तरह से मेहनत करनी होगी और सबका सहयोग लेकर हमें विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों से बाहर लाना होगा। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीई) की संसद के प्रति जवाबदेही के बारे में प्रश्न पूछा जिसके जवाब में प्रधान ने कहा एनटीई की संसद के प्रति



जवाबदेही के बारे में सवाल पूछा गया। इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी गई और मैं इससे संबंधित सवाल का संसद में जवाब दे रहा हूँ, यही तो संसदीय जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि एक निकाय कई तरह की परीक्षाएं ले सके, इसके लिए एनटीई के बारे में सोचा गया। 2017 से शुरुआत हुई और 2018 में इसने आकार लिया। उन्होंने कहा कि छह साल में पांच करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दीं और अच्छे संस्थानों में उन्हें प्रवेश मिला। उन्होंने कहा कि दई सी से अधिक परीक्षाएं हुईं। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समाज

का एक वर्ग है क्योंकि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे और सबकी इच्छा है कि वे आगे बढ़ें। शिक्षा आगे बढ़ने का माध्यम है। प्रधान ने कहा कि जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब देश में मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या 51,000 थी जो दस साल में बढ़ कर एक लाख दस हजार हो गई है। प्रधान ने कहा सरकार सभी तरह की जवाबदेही के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताती है। हमारी सरकार ज्यादातर जिलों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। राजद के प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने

## पिछले 4-5 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में चालीस हजार से अधिक लोगों की नियुक्ति की गई

नई दिल्ली | शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में रिक्रूटमेंट पर 40,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति की है। प्रधान ने कहा कि आईआईटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उद्योग से अनुभवी लोगों को लाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (पीओपी) प्रणाली शुरू की गई है। विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पीओपी आवश्यकता-आधारित होते हैं, न कि यह कोई स्थान है। प्रधान ने कहा कि पीओपी शिक्षा में विशेषज्ञता और नए विचार लाएंगे। प्रधान ने कहा, पीओपी नई शिक्षा नीति के तहत एक प्रमुख सिफारिश है। अब आम सहमति के कि डिग्री के अलावा हमें योग्यता को भी महत्व देना होगा। शिक्षा को रोजगारप्रकट और उद्यमिता की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए, उद्योग और शिक्षा के बीच संबंध आवश्यक है। मंत्री माकपा सदस्य जॉन ब्रिट्टस द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने पीओपी के लिए 10 प्रतिशत शैक्षणिक पद आरक्षित किए हैं और क्या इससे उच्च संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कम हो जाएगा। ब्रिट्टस ने कहा कि लगभग 26 प्रतिशत शैक्षणिक पद और 46 प्रतिशत अन्य पद अभी रिक्त हैं और क्या इस तरह की पीओपी प्रणाली युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को प्रभावित करेगी। प्रधान ने कहा, हमने पिछले 4-5 वर्षों में रिक्रूटमेंट पर 40,000 से अधिक लोगों को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय या कॉलेजों के किसी भी मौजूदा पद पर कब्जा नहीं करेगा। राकांपा सांसद फौजिया खान जानना चाहती थी कि कितनी महिला प्रोफेसरों को पीओपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस पर प्रधान ने कहा कि यह विशेष संस्थानों की आवश्यकता, व्यक्ति की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है।

## केंद्र ने राज्यों को पूर्वव्यापी प्रभाव से खनिजों पर रॉयल्टी वापस करने संबंधी याचिकाओं का विरोध किया

नई दिल्ली | (भाषा) केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में उस याचिका का विरोध किया जिसमें खनिज संपन राज्यों ने 1989 से खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर उसके द्वारा लगाई रॉयल्टी वापस करने का अनुरोध किया गया है। केंद्र ने कहा कि उसे राज्यों को पूर्वव्यापी प्रभाव से रॉयल्टी वापस करने के लिए कहने वाले किसी भी आदेश के बहुआयामी प्रभाव होंगे। उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राज्यों के पास खदानों और खनिज बचत वाली भूमि पर कर लगाने का विचार अधिकार है और खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से खनिज संपन राज्यों के रॉयल्टी वृद्धि होगी। लेकिन इससे फैसले के क्रियान्वयन के संबंध में एक और विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ खनिज संपन राज्यों ने शीर्ष अदालत से इस फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया ताकि वे केंद्र से रॉयल्टी वापस मांग सकें। बहरहाल, केंद्र ने ऐसे किसी आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इसका बहुआयामी प्रभाव होगा।

के आकलन की एक व्यवस्था होती है और तय किया जाता है कि प्रश्न कैसे हों। यह आकलन समय-समय पर किया जाता है।

## वायनाड में भूस्खलन को लेकर तेजस्वी सूर्या की टिप्पणी के बाद लोस में विपक्ष का हंगामा

नई दिल्ली | (भाषा) लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने उस समय हंगामा किया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने केरल के वायनाड में अतिक्रमण को लेकर प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए तथा नेता प्रतिपक्ष रहलु गांधी को भी परोक्ष रूप से निशाने पर लिया। सदन में नियम 197 के तहत प्राकृतिक आपदा पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए सूर्या ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में केरल में कई प्राकृतिक आपदाएं खासकर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं जिनमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई है।



ने उठाया तो उनका टिकट काट दिया गया। सूर्या ने कहा कि वायनाड से पांच साल तक संसद रहे नेता ने वहां की प्राकृतिक आपदा को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई। इसके बाद विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराधन तीन बजकर करीब 50 मिनट पर शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर कांग्रेस सांसद केशी वेणुगोपाल ने कहा कि तेजस्वी सूर्या को इस दुखद

घटना पर राजनीति करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस त्रासदी पर विपक्ष की तरफ से किसी ने राजनीति नहीं की, लेकिन सत्तापक्ष के सांसद से राजनीति की है... उन्होंने रहलु गांधी के बारे में सवाल खड़े किए हैं। रहलु गांधी ने वायनाड में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कितनी बार आवाज उठाई है, इसका रिकॉर्ड देखा जा सकता है। वेणुगोपाल का कहना था, वायनाड, केरल और भारत के लोग रहलु गांधी को प्यार करते हैं। वह वायनाड से 3.6

लाख से अधिक मतों से जीते हैं। बिरला ने कहा कि सूर्या के भाषण में जो बात इस सदन और देश की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगी उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इससे पहले, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नित्यानंद राय ने कहा कि आपदाओं के प्रबंधन के लिए 33 दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें बाढ़ और भूस्खलन से संबंधित दिशानिर्देश भी शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के कई कदमों का उल्लेख किया और कहा कि 350 जिलों में आपदा के बचाव हेतु स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए योजना शुरू कर गई है और लगभग एक लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। राय का कहना था कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए नियमित रूप से मांक अभ्यास और जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 23 जून, 2024 को गृह मंत्री की अध्यक्षता में सभी केंद्रीय एजेंसियों की बैठक की गई, जिसमें सभी राज्यों को जरूरी मदद देने के लिए कहा गया है।

## भारत में कई गुना बढ़ गई है रोहिंय्या घुसपैट

गुवाहाटी | (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमेंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि भारत में रोहिंय्या घुसपैट काफी बढ़ गई है तथा जनसांख्यिकी में बदलाव आने का खतरा वास्तविक और गंभीर है। शर्मा ने यह संवाददाता सम्मेलन में कहा, रोहिंय्या लगातार भारत-बांग्लादेश सीमा का इस्तेमाल करके भारत में आ रहे हैं और कई राज्य जनसांख्यिकीय बदलाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम, भारत-बांग्लादेश सीमा के केवल एक हिस्से की पहरेदारी कर रहा है, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र अभी भी खुला है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकारें इन घुसपैटियों के प्रति नरम रुख अपना रही हैं और इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। शर्मा ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) से बयान दिया था कि राज्य बांग्लादेश से आने वालों को शरण देगा, जिसका पड़ोसी देश की सरकार ने भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि असम



और त्रिपुरा सरकारों ने इस मामले में कड़े कदम उठाए हैं और दोनों राज्यों की पुलिस ने कई मोकों पर कई रोहिंय्या घुसपैटियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, असम अब रोहिंय्या के लिए सुरक्षित पनाहाह नहीं रहा, क्योंकि हम नरम नीति नहीं अपनाते। हमारी स्थिति पश्चिम बंगाल और झारखंड से बेहतर है। असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के सत्ता में आने के बाद से स्थिति खराब नहीं हुई है।



